



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2018]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 9 जनवरी, 2018

(19 पौष, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 1/के०अ० 30/2013/धा० 109/2018, दिनांक 3 जनवरी, 2018— हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	3—73
भाग IV	शुद्धि—पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग -III**हरियाणा सरकार**

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जनवरी, 2018

संख्या का०आ० 1/के०अ० 30/2013/धा० 109/2018 — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 112 के साथ पठित धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 52/के०अ० 30/2013/धा० 109/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2017 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

अध्याय— I**सामान्य**

1. (1) ये नियम हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2018 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
- (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
- (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;— परिभाषाएं।
 - (क) “आधार प्रमाणीकरण सेवा” से अभिप्राय है, भारत के अनन्य पहचान प्राधिकरण (यू०आई०डी०ए०आई०), या उस द्वारा नियुक्त अभिकरणों द्वारा, किसी व्यक्ति के अनुरोध पर या उसकी सहमति से उसकी जीवसांख्यिकी सूचना (यू०आई०डी०ए०आई०) के अपने केन्द्रीय सरवर (सेवक) में, उस द्वारा अनुरक्षित सूचना से मिलान करने के बाद किया गया इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणित तथा इसमें उस व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना तथा फोटो अथवा “हां/नहीं” अनुक्रिया (जवाब) या प्रतिक्रिया शामिल है;
 - (ख) “आधार संख्या” से अभिप्राय है, भारत के अनन्य पहचान प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति से सम्बंधित जनसांख्यिकी तथा जीवसांख्यिकी सूचना के डी-डूब्लिकेशन (अद्विगुणन) के बाद उत्पन्न तथा जारी बारह अंक की अनन्य पहचान संख्या;
 - (ग) “अधिनियम” से अभिप्राय है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30);
 - (घ) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग;
 - (ङ) “जिला कलक्टर” से अभिप्राय है, सम्बद्ध जिले का कलक्टर या जिला कलक्टर के कृत्यों को करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी;
 - (च) “विशेषज्ञ समूह” से अभिप्राय है धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह;
 - (छ) “प्ररूप” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (ज) “सरकार” से अभिप्राय है, अपेक्षक निकाय के लिए भूमि के अर्जन से सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (झ) “प्रकाशित” से अभिप्राय है,—
 - (i) राजपत्र में प्रकाशित;
 - (ii) अर्जन के अधीन क्षेत्र में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित, जिसमें कम से कम एक स्थानीय देशी भाषा में होगा;

- (iii) प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर पंचायत घर, चौपाल, पटवार घर, धर्मशालाएं, सामुदायिक केन्द्र, नगरपालिका, नगर निगम, जिला कलक्टर, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) तथा तहसील के कार्यालय, जैसी भी स्थिति हो, में अधिसूचना चिपका कर यदि भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण की ओर से अर्जित की गई है, तो अधिसूचना उनके कार्यालयों में भी चिपकाई जाएगी;
- (iv) आम जनता को सूचित करने के लिए ढोल पिटवा कर घोषणा का अनुकरण करके मुनादी करवाई जाएगी; तथा
- (v) सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जानी है:
परन्तु परिसीमा, यदि कोई हो, के गणना के लिए उपरोक्त यथा वर्णित किसी अन्य ढंग के प्रकाशन की अन्तिम तिथि सुविचारित की जाएगी।
- (ज) “धारा” से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;
- (ट) “सामाजिक समाघात निर्धारण” से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन किया गया निर्धारण;
- (ठ) “सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना” से अभिप्राय है, धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार योजना;
- (ड) “सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई” से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित कोई सोसाइटी, निगम या कोई अन्य निकाय या सरकार द्वारा प्रत्यापित कोई इकाई जो किसी प्रस्तावित अर्जन के बारे में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने के लिए प्राधिकृत है;
- (ढ) ‘शहरी क्षेत्र’ से अभिप्राय है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 त के खण्ड (घ) के अधीन नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय- II

भूमि अर्जन हेतु अनुरोध

भूमि के अर्जन हेतु मांग।
धारा 4

3. (1) कोई अपेक्षक निकाय या इस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत इसके प्रतिनिधि, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्ररूप- I में सम्बद्ध जिला कलक्टर को मांग दायर करेगा, अर्थात्:-

- (i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;
- (ii) प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारों के अभिलेख तथा राजस्व नक्शों की तीन प्रतियां;
- (iii) भूमि के वर्गीकरण के बारे में यथा उपलब्ध सूचना अर्थात्, सिंचित बहु-फसल, एकल फसल, बंजर भूमि, इत्यादि;
- (iv) जिला कलक्टर द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(2) जहां अपेक्षक निकाय सरकार है, तो अनुरोध सम्बद्ध विभाग के सचिव या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया जाएगा।

मांग प्राप्त करने पर जिला कलक्टर द्वारा कार्रवाई।
धारा 4

4. (1) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन मांग प्राप्त करने पर, जिला कलक्टर निम्नलिखित के बारे में प्रारम्भिक जांच करने के लिए अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों सहित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए तथा जिला कलक्टर को रिपोर्ट देने के लिए सभी सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों से मिलकर बनने वाली एक समिति गठित करेगा, जैसा वह आवश्यक समझे:-

- (i) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन अनुरोध में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे की शुद्धता;
- (ii) परियोजना के लिए अपेक्षित यथार्थ न्यूनतम भूमि ;
- (iii) क्या अनुरोध अधिनियम के उपबन्धों के संगत है,
और जिला कलक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट में उसकी निम्नलिखित विषयों पर उसकी राय भी शामिल होगी, अर्थात्:-

- (i) कि प्रस्तावित भूमि अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है;
 - (ii) कि अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है;
 - (iii) कि किसी आनुकल्पिक एकान्तर स्थान पर भूमि का अर्जन विचारा गया तथा साध्य नहीं पाया गया;
 - (iv) कि यहां कोई भी अनुपयोजित भूमि परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई है; और
 - (v) कि पूर्व में अर्जित तथा अनुपयोजित पड़ी रही भूमि, यदि कोई हो, का उपयोग ऐसे लोक प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- (3) यदि जिला कलक्टर की उप-नियम (2) में निर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट, उसके पास उपलब्ध अन्य सूचना तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के आधार पर सन्तुष्टि हो जाती है कि मांग अधिनियम के उपबन्धों से संगत है, तो उस सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय—III

सामाजिक समाघात निर्धारण

5. (1) सरकार जिला कलक्टर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट होने के पश्चात् प्रभावित क्षेत्र में सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श प्रारम्भ करने के लिए तथा इन नियमों के प्ररूप-II के भाग-क के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने के लिए अधिसूचना प्रकाशित करेगी:
- परन्तु ऐसी अधिसूचना नियम 7 के अधीन यथा अवधारित, अपेक्षक निकाय द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया फीस जमा कराने के तीस दिन के भीतर प्रकाशित की जाएगी।
- (2) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रभावित कुटुम्बों के विचारों का पता लगाने के लिए लोक सुनवाई हेतु तिथि, समय तथा स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करके प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई, जिसे सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा, द्वारा अनुसरित धारा 4 के प्रयोजनों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के साथ परामर्श से किया जाएगा।
- (3) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट इसकी प्रारम्भ की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर सरकार को प्ररूप-III में प्रस्तुत की जाएगी तथा इसमें प्रभावित कुटुम्बों के अभिलिखित विचार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (4) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात को ठीक करने के लिए अपनाए जाने वाले अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सहित प्ररूप-IV में भी प्रस्तुत की जाएगी।
- (5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना प्रकाशित की जाएगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन।
धारा 4, 5, 6

6. सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:-
- (क) अर्हक सामाजिक समाघात निर्धारण संसाधन भागीदारों तथा व्यवसायियों के डाटाबेस बनाएगी तथा सतत रूप से विस्तारित करेगी जो भूमि अर्जन तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण का संचालन करने हेतु अपेक्षित निपुणता तथा क्षमता सहित व्यक्तिगत तथा संस्था के नेटवर्क के रूप में काम करेगी;
 - (ख) सरकार के सामाजिक समाघात निर्धारण करवाने के अनुरोध पर परियोजना-विशिष्ट सन्दर्भ की शर्तें तैयार करते हुए तुरन्त कार्यवाही करेगी ;
 - (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम तथा सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम करना तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित निर्देशिका, उपकरण मामलों की तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना;
 - (घ) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यथा अपेक्षित निरन्तर सहायता तथा सुधारात्मक कार्यवाई उपलब्ध कराना;
 - (ङ) सुनिश्चित करेगी कि नियम 22 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन तथा पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली हेतु संव्यवहार आधारित वैब आधारित कार्यगति अनुरक्षित की जा रही है तथा कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सभी सुसंगत दस्तावेज़ प्रकट किए गए हैं;
 - (च) सभी सामाजिक समाघात निर्धारण तथा सम्बद्ध प्राथमिक सामग्री की सूची रखेगी; तथा
 - (छ) सामाजिक समाघात निर्धारण की गुणवत्ता तथा उन्हें करने के लिए उपलब्ध क्षमताओं का सतत रूप से पुनरीक्षण, मूल्यांकन तथा सुदृढीकरण करेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए संस्थागत सहायता तथा सरलीकरण।
धारा 4.

परियोजना
निर्देश के
विशिष्ट निबन्धन
और सामाजिक
समाघात
निर्धारण के
लिए प्रक्रिया
फीस।
धारा 4 (5)

7. (1) जहां सरकार का भूमि अर्जन करने का आशय हो, ऐसे भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को सभी दस्तावेजों सहित भेजी जाएगी, जो,—

(क) भूमि अर्जन के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए विस्तृत परियोजना निर्देश के विशिष्ट निबन्धन तैयार करेगी, सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध करेगी जो इन नियमों के प्रारूप-11 के भाग-ख में यथा निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समुचित टीम आकार (तथा क्षेत्रीय टीम की संख्या) तथा टीम के सदस्यों का ब्योरा सूचीबद्ध करते हुए कार्यान्वित करनी होगी तथा वितरण करने योग्य की (कुंजी) की समय सारणी तथा अन्तिम तिथि अनुबन्ध करना।

(ख) प्रत्येक मद या कार्यकलाप की लागतों के स्पष्ट विघटन सहित निर्देश निबन्धनों पर आधारित अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण फीस अवधारित करना। फीस की राशि क्षेत्र, परियोजना की किस्म तथा प्रभावित कुटुम्बों की संख्या सहित सरकार द्वारा परिभाषित मापदण्डों (पैरामीटर) पर आधारित होगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण फीस का दस प्रतिशत निर्देश निबन्धन, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार करने तथा उसे सरकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रशासकीय खर्च के रूप में सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को आवंटित की जाएगी।

(3) अपेक्षक निकाय प्रयोजन के लिए सम्बद्ध सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के अनुसूचित बैंक खाते में सामाजिक समाघात निर्धारण फीस अग्रिम में जमा करेगी।

सामाजिक
समाघात
निर्धारण टीम
का चयन।
धारा 4

8. (1) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अर्हक सामाजिक समाघात निर्धारण साधन भागीदारों तथा व्यवसायियों के डाटाबेस में रजिस्टर्ड या पैनलित व्यक्तियों तथा संस्थाओं से प्रत्येक परियोजना के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण टीम का चयन करने के लिए जिम्मेवार होगी।

(2) अपेक्षक निकाय को सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए नियुक्त की जा रही सामाजिक समाघात निर्धारण टीम की नियुक्ति में किसी भी रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम के लिए आकार तथा चयन मापदण्ड सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा विकसित परियोजना विशिष्ट निर्देश निबन्धन के अनुसार होगा।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम का गठन सामाजिक समाघात निर्धारण या सम्बन्धित क्षेत्र आधारित निर्धारण करने के अनुभव वाले व्यक्तियों या संगठन की नियुक्ति द्वारा किया जा सकता है तथा टीम में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं,—

(क) स्वतन्त्र व्यवसायी, अर्हक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, तकनीकी विशेषज्ञ का संयोजन, जो कि प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षक निकाय से सम्बन्धित न हों; तथा

(ख) कम से कम एक महिला सदस्य।

(5) टीम का नेता सम्पूर्ण निर्धारण अवधि के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के साथ सम्पर्क करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण टीम के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि सम्बद्ध परियोजना के निर्धारण के लिए नियुक्त टीम के सदस्यों के हित में कोई प्रतिद्वन्द्व न हो।

(7) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम के सभी सदस्य शपथ पत्र के द्वारा यह परिवचन देंगे कि न तो वह या न ही उसका कोई रक्त-सम्बन्धी अपेक्षक निकाय या परियोजना में किसी अन्य हितधारी से प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई लाभ प्राप्त करेगा।

(8) यदि किसी चरण में, यह पाया जाता है कि कोई टीम का सदस्य या टीम के सदस्य के परिवार का कोई सदस्य अपेक्षक निकाय से या परियोजना में किसी अन्य हितधारक से प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करता है, तो कथित सदस्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित उसके विरुद्ध किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त अयोग्य हो जाएगा तथा सामाजिक समाघात निर्धारण किसी अन्य मामलों में शामिल नहीं किया जाएगा।

सामाजिक
समाघात
निर्धारण करने
की प्रक्रिया।
धारा-4

9. (1) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम मात्रात्मक तथा गुणात्मक डाटा की एक श्रेणी एकत्रित करेगी तथा उसका विश्लेषण करेगी, स्थलों का विस्तृत मुआयना करेगी, भागीदारी पद्धतियों, यथा संकेन्द्रित समूह विचार-विमर्श, भागीदारीपूर्ण ग्रामीण या शहरी मूल्य मूल्यांकन तकनीकें, जैसी भी स्थिति हो, का प्रयोग करेगी तथा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने में सूचक साक्षात्कार करेगी।

(2) सभी सम्बद्ध परियोजना रिपोर्ट तथा व्यवहार्यता अध्ययन यथा अपेक्षित सम्पूर्ण सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के दौरान सामाजिक समाघात निर्धारण टीम को उपलब्ध कराए जाएंगे। सामाजिक समाघात निर्धारण टीम से सूचना के लिए किसी अनुरोध को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा किन्तु दस दिन से अधिक नहीं। जिला कलक्टर सामाजिक समाघात निर्धारण टीम द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सभी सम्बद्ध भूमि अभिलेख तथा डाटा, क्षेत्र सत्यापन, पुनरीक्षण तथा समरूप परियोजनाओं से तुलना के सम्पूर्ण विश्लेषण पर आधारित विस्तृत निर्धारण सामाजिक समाघात निर्धारण टीम द्वारा किया जाएगा। धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन उपबन्धित मामलों के अतिरिक्त निर्धारण में निम्नलिखित का अवधारण किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) दोनों अर्जित की जाने वाली भूमि तथा परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक तथा अन्य समाघातों से प्रभावित क्षेत्रों सहित प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र ;
- (ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा तथा स्थान;
- (ग) क्या अनुसूचित क्षेत्र में अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि निरूप्य अंतिम उपाय के रूप में है;
- (घ) पहले क्रीत, हस्तांतरित, पट्टे पर ली गई या अर्जित भूमि, यदि कोई हो, तथा परियोजना के लिए वांछित भूमि के प्रत्येक भाग का इच्छित प्रयोग;
- (ङ.) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक, अनुपयोजित भूमि के प्रयोग की सम्भावना तथा क्या कोई ऐसी भूमि अधिभोग के अधीन है;
- (च) भूमि की प्रकृति, वर्तमान प्रयोग तथा भूमि का वर्गीकरण तथा यदि यह कृषि भूमि है, तो कथित भूमि की सिंचाई व्याप्ति तथा फसल पद्धति;
- (छ) क्या खाद्य सुरक्षा के सम्बंध में विशेष उपबन्धों का प्रस्तावित भूमि अर्जन में अनुसरण किया गया है;
- (ज) जोत का आकार, स्वामित्व पद्धति, भूमि वितरण, आवासीय मकानों की संख्या, तथा लोक तथा निजि अवसरचना तथा परिसम्पत्तियां; तथा
- (झ) पिछले तीन वर्षों में भूमि की कीमतें तथा भूमि के स्वामित्व, अन्तरण तथा प्रयोग के मामलों में नूतन परिवर्तन।

(4) भूमि निर्धारण, भूमि अभिलेख तथा क्षेत्र सत्यापन के आधार पर सामाजिक समाघात टीम निर्धारण में प्रभावित कुटुम्बों की संख्या तथा उनमें से विस्थापित कुटुम्बों की संख्या का सही अनुमान दिया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि यथा संभव सभी प्रभावित कुटुम्बों को परिगणित किया गया है:

परन्तु जहां गणना सम्भव नहीं है, वहां प्रतिनिधि प्रतिदर्श सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा किया जाएगा।

(5) प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ब्यौरा प्ररूप-।।। के अनुसार उपलब्ध डाटा तथा सांख्यिकीय, क्षेत्रीय मुआयनों तथा परामर्शों के आधार पर तैयार करनी चाहिए:

परन्तु उन परियोजनाओं में जहां पुनर्व्यवस्थापन अपेक्षित है, वहां चिन्हित पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का मुआयना किया जाएगा तथा भूमि की संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा तथा इसकी वर्तमान निवासी जनसंख्या इंगित की जाएगी।

(6) उपरोक्त सूचीबद्ध प्रक्रिया में संगृहित डाटा के आधार पर तथा प्रभावित समुदायों तथा मुख्य हितधारियों के परामर्श से सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई प्ररूप-।।। के अनुसार प्रस्तावित परियोजना तथा भूमि अर्जन से सम्बद्ध सकारात्मक तथा नकारात्मक सामाजिक समाघातों की प्रकृति, सीमा तथा मात्रा की पहचान की जाएगी तथा निर्धारण किया जाएगा।

- (7) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया में सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना, जो निर्धारण की प्रक्रिया में चिन्हित सामाजिक समाघातों को ठीक करने के लिए अपनाए जाने वाले सुधारक उपायों को प्रस्तुत करेगी, शामिल है।
- (ii) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम को लागतों, समय सीमा तथा क्षमताओं के स्पष्ट सूचक सहित समाघात अल्पीकरण तथा प्रबन्ध कौशल की व्यवहार्यता का निर्धारण करना चाहिए।
- (iii) सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना में निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे, अर्थात्:-
 - (क) जो अधिनियम के मसौदे के अनुसार, प्रभावित परिवारों के सभी प्रवर्गों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निबन्धनों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है;
 - (ख) जो अपेक्षक निकाय ने कथित किया है कि इसे परियोजना प्रस्ताव तथा अन्य सम्बद्ध परियोजना दस्तावेजों में अपनाया जाएगा ; तथा
 - (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया तथा लोक सुनवाई के निष्कर्ष के उत्तर में अपेक्षक निकाय द्वारा अपनाए जा रहे अन्य उपाय।

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम में अल्पीकरण उपायों सहित प्रस्तावित परियोजना तथा भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों तथा सामाजिक लागतों तथा लाभों के बकाया तथा उसके वितरण का निर्णायक निर्धारण मुहैया कराना चाहिए तथा निर्धारण के सम्बंध में मुहैया करना चाहिए कि क्या प्रस्तावित परियोजना से लाभ उसकी सामाजिक लागतों से अधिक है तथा प्रतिकूल सामाजिक समाघात जो प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किए जाने सम्भावित हैं या प्रस्तावित अल्पीकरण उपायों के बाद प्रभावित परिवार कथित भूमि अर्जन तथा पुनर्व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक या सामाजिक रूप से बदतर होने के जोखिम में रहेंगे।

सामाजिक
समाघात
निर्धारण रिपोर्ट
तथा सामाजिक
समाघात प्रबन्ध
योजना की
प्रस्तुति। धारा 6

10. अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी तथा स्थानीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) तथा तहसीलदार के कार्यालयों में भेजी जाएगी तथा प्रकाशित भी कराई जाएगी।

सामाजिक
समाघात
निर्धारण रिपोर्ट
तथा सामाजिक
समाघात प्रबन्ध
योजना।
धारा 4(6)

11. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना का किसी एकल दस्तावेज़ में सभी सुसंगत सूचना तथा विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए सूत्रबद्ध की जाएगी तथा लिखित रूप से लघुकृत अर्थात् स्पष्ट संक्षिप्त तथा पहुंच विशेष रूप से प्रभावित परिवारों के सदस्यों की पहुंच में होगी।

लोक सुनवाई
करने के लिए
प्रक्रिया। धारा 5

12. (1) प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों को प्रकट करने, निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया मांगने के लिए तथा अतिरिक्त सूचना तथा विचार मांगने हेतु की जाएगी ताकि इन्हें अन्तिम दस्तावेज़ों में सम्मिलित किया जा सके।

(2) लोक सुनवाई प्रभावित क्षेत्र में अथवा लोक सुनवाई के लिए पहुंच की सुगमता, साधनों, अवसरचना इत्यादि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर यथा सम्भव की जाएगी। प्रभावित क्षेत्र के निकट यदि प्रभावित क्षेत्र में एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं तो लोक सुनवाई प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारियों में की जाएगी जिसके भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि स्थित है।

(3) लोक सुनवाई की तिथि, समय तथा स्थान प्रारूप-V में नोटिस के रूप में सुनवाई की ऐसी तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा प्रकाशित करवाया जाएगा।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का प्रारूप लोक सुनवाई से तीन सप्ताह पूर्व प्रकाशित किया जाएगा तथा सभी प्रभावित स्थानीय प्राधिकारियों में वितरित किया जाएगा। रिपोर्ट के प्रारूप की एक प्रति जिला कलक्टरों के कार्यालय को भेजी जाएगी। अपेक्षक निकाय को भी रिपोर्ट के प्रारूप की एक प्रति दी जाएगी। रिपोर्ट की पर्याप्त प्रतियां तथा सारांश (संक्षिप्त विवरण) लोक सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जाएंगी। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों को सांझा करने हेतु सुलभ प्रदर्शन तथा अन्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम का सदस्य लोक सुनवाई को सुकर बनाएगा जो कि सरकारी अधिकारियों अर्थात् उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक)/तहसीलदार जैसा भी विनिर्दिष्ट किया जाए, सहित स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित की जाएगी। स्थानीय प्राधिकारियों में लोगों के लोक प्रतिनिधियों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में लोक सुनवाई की व्यवस्था के बारे में सभी निर्णय करने में भी शामिल किया जाएगा।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रतिभागी समझ सकें तथा अपना मत व्यक्त कर सकें सभी कार्यवाही प्रभावी तथा विश्वसनीय अनुवादकों की सहायता से यदि आवश्यक हो, स्थानीय भाषा में की जाएगी।

(7) अपेक्षक निकाय तथा भूमि अर्जन तथा पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन पदाधिकारियों यथा विषय से सम्बन्धित नायब तहसीलदार/कानूनगों इत्यादि भी लोक सुनवाई में हाजिर होंगे तथा प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा सरोकारों का समाधान करेंगे।

(8) लोक प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों तथा मीडिया को भी लोक सुनवाई में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा।

(9) लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की विडियो रिकार्डिंग की जाएगी तथा तदनुसार उसका प्रतिलेखन किया जाएगा। यह रिकार्डिंग तथा प्रतिलेखन अन्तिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना के साथ प्रस्तुत किये जाएंगे।

(10) लोक सुनवाई की समाप्ति के बाद, सामाजिक समाघात निर्धारण टीम सार्वजनिक सभा में प्राप्त सम्पूर्ण पुनर्निवेशन तथा सभा में एकत्र की गई सूचना का विश्लेषण करेगी तथा तदनुसार संशोधित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में अपने विश्लेषण सहित उसे शामिल करेगी।

(11) सार्वजनिक सभा में उठाए गए प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जाएगा तथा सामाजिक समाघात निर्धारण टीम सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक आक्षेप को सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में विचारा गया है।

13. (1) विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा तथा अपने गठन की तिथि से दो मास की अवधि के भीतर उस बारे में अपनी सिफारिश करेगा।

(2) विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें प्रकाशित की जाएंगी।

विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्य निर्धारण।

धारा 7

14. (1) सरकार जिला कलक्टर की रिपोर्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें, यदि कोई हों, की जाँच करेगी तथा अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्र का निर्णय करेगी जो कि लोगों का न्यूनतम विस्थापन, अवसररचना की न्यूनतम बाधा, प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित करे।

(2) उप नियम(1) के अधीन सरकार का निर्णय प्रकाशित किया जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह इत्यादि की सिफारिशों पर विचार। धारा 7.

अध्याय-IV

सहमति

15. (1) लोक निजी (प्राइवेट) साझेदारी परियोजनाओं तथा निजी (प्राइवेट) कम्पनियों के मामलों में, जिला कलक्टर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण टीम के परामर्श से ऐसे सभी भू-स्वामियों की सूची तैयार की जाएगी जिनसे सहमति प्राप्त की जानी है। सूची सहमति प्राप्त करने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रकाशित की जाएगी।

प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति।

धारा 2(2).

(2) किसी आक्षेप के मामले में, आक्षेपकर्ता के विचार पर विचार किया जाएगा। अस्वीकृति की दशा में, ऐसा करने के कारण लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे तथा दस दिन के भीतर सम्बद्ध व्यक्ति को सूचित किये जाएंगे।

(3) जिला कलक्टर स्थानीय प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम तीन सप्ताह अग्रिम में तिथि, समय तथा स्थान अधिसूचित करेगा।

(4) अपेक्षक निकाय द्वारा सम्मत प्रस्तावित निबन्धन तथा शर्तें भी प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामी को, प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक के कम से कम तीन सप्ताह अग्रिम में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) अपेक्षक निकाय या उसके प्रतिनिधि, जो पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन तथा मुआवजे के निबन्धनों का निर्णय तथा बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे सभी प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे तथा प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उठाए प्रश्नों का जवाब देंगे। अपेक्षक निकाय द्वारा वचनबद्ध पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन, मुआवजे के निबन्धन तथा शर्तें स्थानीय भाषा में सदस्यों को समझाई जाएंगी तथा सदस्यों तथा अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर प्राप्त किए जाएंगे।

(6) बैठक की समाप्ति पर प्रत्येक व्यक्तिगत भू-स्वामी को हस्ताक्षरित घोषणा में सूचित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह अन्तर्ग्रस्त भूमि के अर्जन के लिए सहमति देता है / देती है या देने से इन्कार करता है/करती है। इस घोषणा के साथ निबन्धन तथा शर्तें सलग्न करके इस घोषणा की एक प्रति सम्बद्ध भू-स्वामी को दी जाएगी। घोषणा जिला कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।

(7) जो प्रभावित भू-स्वामी बैठक में हाजिर नहो सके वे भू-स्वामियों की बैठक की तिथि से इक्कीस दिन के भीतर जिला कलक्टर को अपनी हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। घोषणा प्ररूप जिला कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा तथा घोषणा के साथ निबन्धन तथा शर्तें सलग्न करके उसकी एक प्रति प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी।

(8) भू-स्वामियों की बैठक की बैठक के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति प्राप्त करने की सभी कार्यवाहियों को विडियों में अभिलिखित की जाएगी तथा सभी कार्यवाहियां लिखित में प्रलेखित करनी होंगी।

(9) सहमति प्रक्रिया के निष्कर्ष प्रकाशित किए जाएंगे।

(10) सामाजिक समाघात निर्धारण टीम के सदस्य प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में सहायता के लिए उपस्थित होंगे।

(11) कोई भी भू-स्वामी उपरोक्त रीति में एकबार दी गई अपनी सहमति वापस नहीं लेगा।

सहमति
कार्यवाहियों में
कलक्टर की
भूमिका तथा
जिम्मेवारी।
धारा 2(2).

16. (1) जिला कलक्टर सहमति प्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान अधिसूचित करेगा तथा सहमति कार्यवाहियों में प्रभावित भू-स्वामियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लोक जानकारी अभियान आयोजित करेगा।

(2) जिला कलक्टर सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक भू-स्वामी जिससे सहमति मांगी गई है, को कम से कम तीन सप्ताह अग्रिम में स्थानीय भाषा में निम्नलिखित मुद्दे कराया जा रहा है, अर्थात् :-

- (क) स्थानीय भाषा में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट (यदि सहज ही उपलब्ध है) के प्रारूप की एक प्रति;
- (ख) मुआवजा तथा पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित आरम्भिक पैकेज ;
- (ग) राजस्व विधियों, वन अधिकार अधिनियम तथा अन्य विधानों के अधीन गांव तथा इसके निवासियों द्वारा साधारणतः उपभोगित अधिकारों की एक सूची;
- (घ) कलक्टर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन, यह प्रमाणित करते हुए कि यदि परियोजना के लिए सहमति इनकार की जाती है, तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा तथा यह अभिव्यक्त करते हुए कि सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से बल प्रयोग करना या डराने का कोई प्रयास गैरकानूनी होगा;
- (ङ) सहमति प्रक्रिया की घोषणा हस्ताक्षर करने के लिए बल प्रयोग करने के किसी प्रयास के मामले में सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारी या प्राधिकारी के दूरभाष संख्या सहित सम्पर्क ब्योरे ;

(3) जिला कलक्टर भू-स्वामियों की बैठकों में हाजिर होगा।

(4) जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित सभी दस्तावेज प्रभावित भू-स्वामी को उपलब्ध कराए गए हैं तथा कोई चाही गई सूचना सात दिन के भीतर उपलब्ध कराएगा।

सहमति
कार्यवाहियों के
लिए अपेक्षक
निकाय की
भूमिका तथा
जिम्मेवारियां।
धारा 2.

17. (1) अपेक्षक निकाय मुआवजों तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के निबन्धन तथा शर्तों का निर्णय करने तथा बातचीत करने के लिए सक्षम प्रातिनिधियों को नियुक्त करेगा, जो सहमति प्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में हाजिर रहेंगे तथा भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे।

(2) अपेक्षक निकाय सहमति तथा कोई अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, प्राप्त करने से पूर्व परियोजना के सम्बन्ध में सभी सूचनाएं मुद्दे कराएगा।

(3) प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति प्रारूप-VI में प्राप्त की जाएगी।

अध्याय-V

भूमि अर्जन तथा पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के लिए प्रारम्भिक अधिसूचना

प्रारम्भिक
अधिसूचना का
प्रकाशन।
धारा 11.

18. (1) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को पूरा करने के बाद तथा प्रभावित परिवारों की सहमति प्राप्त करने बाद, जब कभी अपेक्षित हो, यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि भूमि किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्र में अपेक्षित है या सम्भाव्यतः अपेक्षित है तो धारा 11 में निर्दिष्ट प्रारम्भिक अधिसूचना प्रारूप-VII में प्रकाशित की जाएगी।

(2) धारा 11 के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, कलक्टर इसके नीचे यथा विनिर्दिष्ट अद्यतन भूमि अभिलेखों को पूरा करना सुनिश्चित करेगा :-

- (क) मृतक व्यक्तियों के नामों को काटना ;
- (ख) मृतक व्यक्तियों के विधिक वारिसों के नाम लिखना ;
- (ग) भूमि में अधिकारों जैसे कि विक्रय उपहार, विभाजन इत्यादि के पंजीकृत लेन-देनों को प्रभावी करना ;
- (घ) भूमि अभिलेखों में रहन की सभी प्रविष्टियां करना ;
- (ङ) रहन की प्रविष्टियों को काटना यदि बंधकित सम्पति विलेखों के रजिस्टर्ड पुन-हस्तांतरण द्वारा लिए गए कर्जों के सम्पूर्ण भुगतान के लिए उधार देने वाले अभिकरण द्वारा पत्र जारी किया गया है;
- (च) सभी प्रचलित वन कानूनों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियां करना ;
- (छ) सरकारी भूमि के मामलों में आवश्यक प्रविष्टियां करना और स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि के सम्बन्ध में भी आवश्यक प्रविष्टियां करना;
- (ज) भूमि की परिसम्पति जैसे कि निर्माण, भवनों, वृक्षों, कुओं इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियां करना ;

- (झ) भूमि में शेयर उत्पादकों की आवश्यक प्रविष्टियाँ करना ;
- (ज) उगी हुई या बीजी हुई और ऐसी फसलों के क्षेत्र की आवश्यक प्रविष्टियाँ करना; तथा
- (ट) कोई अन्य सम्बद्ध प्रविष्टियाँ।

19. (1) कलक्टर प्ररूप-VIII में नोटिस जारी करने के बाद तथा धारा 15 की उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित सभी आक्षेपों की सुनवाई तथा जाँच करने के बाद सरकार को उक्त उपधारा के अधीन उसके निर्णय के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आक्षेपों की सुनवाई। धारा 15.

(2) कलक्टर की रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होगा, अर्थात् :-

- (क) क्या प्रस्तावित अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन को पूरा करता है के सम्बन्ध में उपयुक्तता निर्धारण ;
- (ख) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना की आवश्यकता की आत्यंतिक केवल-न्यूनतम सीमा है;
- (ग) क्या वैकल्पिक स्थान पर भूमि अर्जन विचारा गया है तथा उपयुक्त नहीं पाया गया है के सम्बन्ध में उपयुक्तता;
- (घ) कोई भी ऐसी अप्रयुक्त भूमि नहीं है जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई है;
- (ङ) पहले अर्जित भूमि, यदि कोई हो, तथा जो अनुपयोजित रही है ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई है तथा उसके सम्बन्ध में सिफारिशें ;
- (च) आक्षेपों पर उपयुक्तता बारे सिफारिशें;
- (छ) कार्यवाहियों के उपयुक्तता अभिलेख;
- (ज) भूमि अर्जन की अनुमानित लागत के सम्बन्ध में उपयुक्तता ;
- (झ) पुनर्वास के लिए संभाव्य प्रभावित परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरे।

20. (1) धारा 11 की उप धारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ऐसी प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि के भीतर प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराएगा तथा जनगणना कराएगा। पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तथा सार्वजनिक सुनवाई की तैयारी। धारा 16.

(2) प्रशासक द्वारा करवाए जाने वाले प्रभावित परिवारों के सर्वेक्षण तथा करवाई जाने वाली जनगणना के प्रयोजन के लिए, वह धारा 16 की उप-धारा (1) में यथा वर्णित कारकों के अतिरिक्त निम्नलिखित को विचार में रखेगा,—

- (क) सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट ;
- (ख) स्थानीय प्राधिकरणों के अभिलेख तथा अन्य सरकारी अभिलेख।

(3) प्रशासक प्रभावित परिवारों को घर-घर निरीक्षण से तथा प्रभावित क्षेत्र में अवसंरचना परियोजना के मामलों में, स्थल निरीक्षण से डाटा सत्यापित करवाएगा।

(4) प्रशासक द्वारा तैयार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रारूप में, धारा 16 की उप-धारा (2) में वर्णित ब्योरों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात् :-

- (क) प्रभावित परिवारों के सदस्यों की आधार संख्या, यदि उपलब्ध है, सहित इनकी सूची ;
- (ख) विस्थापित परिवारों के सदस्यों की आधार संख्या, यदि उपलब्ध है, सहित इनकी सूची ;
- (ग) प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना की सूची ;
- (घ) प्रभावित क्षेत्रों में भूमि जोतों की सूची ;
- (ङ) अर्जित की जाने वाली भूमि तथा भवन से संलग्न वृक्षों, निर्माणों, अन्य अचल सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों की सूची ;
- (च) प्रभावित क्षेत्रों में व्यापारों या कारबारों की सूची ;
- (छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों से संबंधित व्यक्तियों की सूची ;
- (ज) प्रभावित क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सूची;
- (झ) प्रभावित परिवारों के बेरोजगार युवाओं की सूची ; तथा

(ज) पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को लागू करने के लिए समय सीमा:

परन्तु यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसका ऐसा आधार बनवाने के प्रयास किए जाएंगे बशर्ते कि वह ऐसे नामांकन के लिए अपनी सहमति देता है तथा प्रभावित परिवारों के दावों को सहमति-आधारित आधार प्रमाणीकरण सेवा कार्यान्वित करके उसे सुकर बनाया जा सकता है। ;

(5) प्रशासक व्यापक तथा विस्तृत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप प्रकाशित करेगा।

(6) प्रशासक या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार कथित नोटिस में वर्णित तिथि, समय तथा स्थान पर तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस जारी करके प्रभावित क्षेत्र में जो यथावश्यक परिवर्तन सहित सार्वजनिक सुनवाई पर भी लागू होंगे, सार्वजनिक सुनवाई करेगा।

अनुमोदित पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन का प्रकाशन। धारा 18.

21. धारा 17 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कलक्टर द्वारा पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के पुनरीक्षण के बाद तथा अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार आयुक्त द्वारा स्कीम के अनुमोदन के बाद, अनुमोदित पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त द्वारा प्रभावित क्षेत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा आयुक्त अनुमोदित पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रकाशन के बारे में धारा 50 के अधीन गठित राज्य निगरानी समिति को भी सूचित करेगा।

वैब आधारित कार्य-गति तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली।

22. सरकार एक समर्पित, उपभोक्ता मैत्रिपूर्ण वेबसाइट सृजित करेगी जो लोकमंच (प्लेटफॉर्म) के रूप में काम (सेवा) करेगी जिस पर प्रत्येक अर्जन मामले का सम्पूर्ण कार्य-गति, सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना से आरम्भ तथा निर्णय तैयार करने, लागूकरण तथा संपरीक्षा (ऑडिट) के प्रत्येक स्तर की कार्यवाही को उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए विकास योजना। धारा 41.

23. अपेक्षक निकाय की ओर से भूमि अर्जन करने वाली परियोजना के मामले में तैयार की जाने वाली विकास योजना, जिसमें धारा 41 में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल है, प्रारूप IX के अनुसार होगी।

अध्याय-VI

घोषणा तथा अवार्ड

अर्जन के लिए घोषणा का प्रकाशन। धारा 19.

24. धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथा उपबन्धित कलक्टर की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद तथा आक्षेपों की जांच तथा उस पर निर्णय करने के बाद पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के संक्षिप्त विवरण (सारांश) सहित धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि के अर्जन के लिए एक घोषणा सरकार द्वारा प्रारूप-X में प्रकाशित की जाएगी।

मुआवजे का अवधारण। धारा 26-30

25. (1) मुआवजा, अधिनियम की प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 2 के सामने खाना 3 के अधीन जारी अधिसूचना के साथ पठित धारा 26 से धारा 30 में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) रीति जिसमें अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की मद 9 के अधीन सिंचाई या जल-विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित परिवारों को मछली पकड़ने के अधिकार अनुज्ञात किए जाएंगे, यथा अपेक्षित सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग या कोई अन्य विभाग के परामर्श से मत्स्य विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(3) मुआवजे का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े खाता प्राप्तक चैक (account payee cheque)/इलैक्ट्रॉनिक मेल अन्तरण/साथ-साथ सकल निपटान (RTGS)के माध्यम से किया जाएगा।

(4) जहां कोई अधिक राशि धारा 33 की उप-धारा (3) के अधीन अवार्ड में की गई शुद्धि के परिमाणस्वरूप किसी व्यक्ति को भुगतान की गई साबित होती है तथा ऐसा व्यक्ति उसको किए गए उक्त अधिक भुगतान को वापस करने से इनकार करता हो, तब ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

भूमि अर्जन अवार्ड। धारा 23.

26. कलक्टर धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित तथा दिए गए सार्वजनिक नोटिस के अनुसरण में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उठाए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की जांच तथा निपटान करने के बाद प्रारूप- XI के अनुसार अधिनियम की धारा 23 के अधीन भूमि अर्जन का अवार्ड करेगा।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अवार्ड। धारा 31 तथा 37.

27. (1) कलक्टर प्रारूप-XII में, धारा 31 के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का अवार्ड भी करेगा तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार को परिवारवार अवार्ड देगा।

(2) मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधन के द्वारा प्राप्त किए गए किसी पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन लाभ की वसूली, वापस करने से इनकार करने पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

(3) अधिनियम की तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा मूल न्यूनतम सुख-सुविधाओं का उपबन्ध प्ररूप- XIII में हैं।

अध्याय—VII

प्रशासक, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन समिति तथा राज्य निगरानी समिति

28. उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) या कोई अधिकारी जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत समकक्ष पदवी का कोई अन्य अधिकारी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासक के रूप में कार्य करेगा। प्रशासक की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां होंगी, अर्थात्:—

प्रशासक की शक्तियां, कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां। धारा 43.

- (क) नियम 20 के अनुसार प्रभावित परिवारों तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार द्वारा रखे गए पशुओं के ब्यौरे का सर्वेक्षण तथा गणना करवाना;
- (ख) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करना (जिसे, इसमें, इसके बाद, स्कीम प्रारूप के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ;
- (ग) प्रभावित क्षेत्रों में नियम 20 के उप-नियम (5) के अनुसार स्कीम प्रारूप का व्यापक प्रचार करना;
- (घ) सम्बद्ध व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को स्कीम प्रारूप उपलब्ध कराना;
- (ङ) स्कीम प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन तथा संचालन करना;
- (च) कलक्टर को स्कीम प्रारूप प्रस्तुत करना;
- (छ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का निष्पादन तथा निगरानी करना ;
- (ज) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सामाजिक संपरीक्षा लागू होने के बाद आयुक्त की सहायता करना; तथा
- (झ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम हेतु किए जाने वाले अपेक्षित कोई अन्य कार्य करना।

29. (1) सरकार पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की प्रगति तथा लागूकरण की मोनीटरिंग तथा पुनरीक्षण करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका, नगरपरिषद, या नगर निगम, जैसी भी स्थिति हो, के परामर्श से स्कीम कार्यान्वयन के पश्चात् बाद सामाजिक संपरीक्षा के लिए परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति गठित करेगी।

परियोजना स्तर पर पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन समिति। धारा 45.

(2) जब प्रशासक द्वारा स्कीम प्रारूप तैयार किया जाएगा समिति अपनी पहली बैठक करेगी। समिति स्कीम के प्रारूप पर विचार विमर्श करेगी तथा सुझाव तथा सिफारिशें करेगी। उसके बाद, समिति पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही पूरी होने तक एक मास में एकबार पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की प्रगति का पुनरीक्षण तथा निगरानी करने के लिए बैठक करेगी।

(3) स्कीम के कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए समिति तीन मास में एकबार बैठक करेगी।

(4) समिति प्रभावित क्षेत्र में जा सकती है तथा प्रभावित परिवारों से चर्चा कर सकती है तथा यदि समिति ऐसा चाहे तो पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया की मोनीटरिंग के लिए पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी जा सकती है।

(5) समिति के सदस्य संयोजक की सरकार द्वारा मुहैया करवाये गये अधीनस्थ अधिकारियों तथा अमले द्वारा सहायता की जाएगी।

(6) समिति के सदस्य सरकार के श्रेणी-I अधिकारियों को अनुज्ञेय दर पर यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे तथा राशि, अपेक्षक निकाय जिससे अर्जन का अनुरोध प्राप्त हुआ है द्वारा इन प्रयोजनों के लिए मुहैया निधि से, जिला कलक्टर द्वारा भुगतान की जाएगी।

30. (1) राज्य मोनीटरिंग समिति धारा 18 के अधीन आयुक्त द्वारा अनुमोदित स्कीमों के प्रकाशन के दो मास के भीतर परियोजनाओं के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के लागूकरण का पुनरीक्षण तथा निगरानी करेगी तथा उसके बाद, समिति की बैठक, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के लागूकरण का पुनरीक्षण तथा मोनीटरिंग करने के लिए तीन मास में एक बार की जाएगी।

राज्य निगरानी समिति की कार्यप्रणाली। धारा 50(3).

(2) उप नियम(1) प्रयोजनों के लिए, समिति,—

- (क) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के अभिलेख तथा सूचना मांग सकती है;
- (ख) जब कभी अपेक्षित हो विचार-विमर्श के लिए अपेक्षक निकाय को बुला सकती है;
- (ग) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति से उसके निर्णय के लागूकरण के बारे में रिपोर्ट की मांग कर सकती है;

(3) राज्य मोनीटरिंग समिति से सम्बद्ध गैर-सरकारी विशेषज्ञों को सरकार के सचिव की पदवी के अधिकारियों को अनुज्ञेय दर पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

अध्याय—VIII

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण

प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते इत्यादि धारा 56.

प्राधिकरण की शक्ति तथा मिथ्या दावे इत्यादि के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों की वसूली। धारा 60 तथा 84.

भूमि के विस्तार की सीमाएं। धारा 2(3)(क).

अनुपयोजित भूमि की वापसी की रीति। धारा 101.

31. प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी तथा रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों तथा अमले के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ सम्यक् परामर्श के बाद सरकार द्वारा पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

32. (1) यदि कलक्टर जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति को धोखे, मिथ्या निरूपण या गैर कानूनी साधनों इत्यादि को अपनाने के कारण गलती से मुआवज़ा दिया गया है, तो कलक्टर गलती करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्राधिकरण को मामला भेजेगा तथा कथित कार्यवाही, उस कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन की जा सकती है।

(2) इस प्रकार खाली की गई भूमि तथा मकान उस परियोजना द्वारा या समुदाय के प्रयोजन के लिए प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपयोग किए जाएंगे।

विविध

33. भूमि के स्वामी से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निजी (प्राइवेट) बातचीत के माध्यम से किसी निजी (प्राइवेट) कंपनी द्वारा खरीद के मामले में अधिनियम के अधीन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के उपबन्धों से बाहर भूमि के विस्तार की सीमाएं ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

34. (1) जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुपयोजित रहती है, तो उसे मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों, जैसी भी स्थिति हो, या सरकार के भूमि अपेक्षक निकाय जिसके लिए भूमि अर्जित की गई थी को नोटिस जारी करते हुए तथा सुनवाई का अवसर देते हुए तथा सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित निबंधन और शर्तों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए स्वतः स्पष्ट आदेश पारित करते हुए मण्डल आयुक्त द्वारा वापस की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन मण्डल आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने के बाद, जिला कलक्टर मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों, जैसी भी स्थिति हो, को या सरकार के भूमि बैंक को उसे वापस करने के प्रयोजन के लिए अर्जित भूमि का कब्ज़ा लेगा तथा सुसंगत अभिलेख में इस बारे में कोई प्रविष्टियां करने के लिए आदेश करेगा।

(3) यदि अपेक्षक निकाय जिला कलक्टर को कथित भूमि का कब्ज़ा नहीं देता तो, जिला कलक्टर अपेक्षक निकाय को पूर्व नोटिस देते हुए कब्ज़ा लेने के लिए सम्बद्ध कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की सहायता लेने के लिए सक्षम होगा।

निरसन।

35. हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2014, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अधीन की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

प्ररूप-1*[देखिए नियम 3 (1)]*

भूमि के अर्जन के लिए अनुरोध

प्रेषक:

नाम

तथा/या अपेक्षक निकाय का पदनाम

सेवा में

1. जिला कलक्टर
2. आयुक्त, आर एण्ड आर,
3.परियोजना/प्रयोजन के लिए एकड़ भूमि अर्जन करने के लिए अनुरोध किया जाता है तथा अर्जित की जाने वाली भूमियां दर्शाने वाला संयुक्त खाके (स्केल में) की तीन प्रतियों सहित अनुबन्ध (अनुबन्धों) I, II तथा III में ब्योरे प्रस्तुत किए जाते हैं। परियोजना की सगर्भता अवधि वर्ष तथा.....मास होगी (केवल तभी लागू होगी यदि सगर्भता अवधि पांच वर्ष से अधिक है)

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एस0आइ0ऐ0) की लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत उपलब्ध है तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित जब कभी आप द्वारा अपेक्षित हो आपके कार्यालय में जमा करवा दी जाएगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि अर्जित की जाने वाली भूमि क्षेत्र में सीमांकित कर दी गई थी तथा सभी आगामी आवश्यक सूचना तथा सहायता आप द्वारा नियत/अनुबन्ध तिथि/समय पर मुहैया करवाई जाएगी।

आपका शुभचिन्तक

अपेक्षक निकाय

अनुबन्ध-I

परियोजना का नाम:-

- (1) गांव का नाम:
- (2) तहसील का नाम:
- (3) नगरपालिका/नगर निगम का नाम:
- (4) जिला का नाम:
- (5) अर्जित किया जाने वाला खसरा संख्या:
- (6) प्रार्थित कुल क्षेत्र (एकड़ों में):
- (7) अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाएं:

पूर्व:-

पश्चिम:

उत्तर:

दक्षिण:

- (8) कृषि तथा सिंचित बहु-फसल भूमि का क्षेत्र (पृथक रूप से वर्णित की जाए)
- (9) कृषि तथा सिंचित बहु-फसल भूमि के समावेश के कारण
- (10) भवन तथा अन्य संरचनाओं, तालाबों, कुओं, वृक्षों इत्यादि के ब्योरे
- (11) अर्जन के लिए धार्मिक भवनों, कब्रिस्तान या मकबरे इत्यादि के समावेश के कारण, यदि कोई हो।

अपेक्षक निकाय

अनुबन्ध-II**परियोजना का नाम:-**

1. विभाग या सरकार या कम्पनी, स्थानीय प्राधिकरण, संस्था:
2. अपेक्षक निकाय का कार्यालय पदनाम :-
3. अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत में) :-
4. क्या अनुरोध सरकार या विभाग द्वारा उसके अपने स्वयं प्रयोग, रखने तथा नियन्त्रण के लिए अधिनियम की धारा 2(1) के अधीन दायर किया गया है :-
5. क्या अनुरोध अधिनियम का धारा 2(1) (क) से 2(1) (च) के अधीन दायर किया गया है :-
6. क्या अनुरोध अधिनियम की धारा 2(2) (क) या (ख) के अधीन दायर किया गया है :-
7. अधिनियम की धारा 3(ग) (i) से (vi) में यथा वर्णित कितने परिवार प्रभावित हुए है :-
8. क्या अनुरोध अधिनियम की धारा 40 के अधीन दायर किया गया है :-
9. यदि ऐसा है, तो किस आधार पर है ?
10. क्या परियोजना के लिए भूमि प्राईवेट बातचीत द्वारा स्वामियों से अंशतः खरीदी गई है :-
11. यदि ऐसा है, तो किस तिथि को तथा किन शर्तों पर (कृपया संक्षेप में बातचीत की शर्तें बताएं तथा उसकी प्रति संलग्न करें) :
12. सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में परियोजना के लिए प्रशासकीय अनुमोदन जारी करने की तिथि (प्रति संलग्न की जानी है) :
13. अनुरोध दायर करने में विलम्ब के कारण, यदि अनुरोध सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में परियोजना के प्रशासकीय अनुमोदन की तिथि से छह सप्ताह के बाद दायर किया गया है :-
14. भूमि का कब्जा कितने समय तक अपेक्षित है :-

अपेक्षक निकाय

अनुबन्ध-III

अपेक्षक प्राधिकारियों द्वारा भूमि के अर्जन के लिए अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र
परियोजना का नाम:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना, जिसके लिए भूमि अर्जित की जानी चाही गई है, का अधिनियम के अधीन अर्जन के लिए विभाग के पत्र संख्या.....दिनांक..... द्वारा प्रशासकीय रूप से अनुमोदन हो गया है (पत्र की प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना की अनुमानित लागतभारतीय रुपये में है तथा आवश्यक बजट स्वीकृत था तथा निधियां अर्जन की लागत के लिए उपलब्ध हैं।
3. विभाग भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण/ उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा डिफ्री के मामले में जब कभी कलक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा पूर्ण राशि का भुगतान करने का वचन देता है।

अपेक्षक निकाय

प्ररूप-II

[भाग क के लिए, देखिए नियम 5(1) तथा भाग-ख के लिए देखिए नियम 7(1)]

भाग क. सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

संख्या.....

चण्डीगढ़ दिनांक.....

चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि की लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सम्भाव्य है अर्थात् ----- के लिए ;

और चूंकि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण कराने का निर्णय किया है;

इसलिए, अब अधिनियम में यथा उपबन्धित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई----- जिला ----- को स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रक्रिया राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

क्षेत्र की अनुसूची

जिला :-

तहसील :-

गांव :-

(उल्लिखित सीमा अनुमानित है)

भूमि की सीमा (एकड़ों में)

सचिव, सरकार

भाग ख. सामाजिक समाघात के लिए निर्देश-निबन्धन तथा प्रक्रिया फीस

- (i) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई सरकार द्वारा भेजे गए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का पुनरीक्षण करेगी तथा परियोजना-विशिष्ट निर्देश निबन्धन तथा बजट प्रस्तुत करेगी। निर्देश-निबन्धन तथा बजट के आधार पर, प्रक्रिया फीस अवधारित की जाएगी, जो अपेक्षक निकाय द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना जारी करने से पूर्व जमा करनी होगी।
- (ii) निर्देश-निबन्धन में निम्नलिखित सूचना शामिल होगी:—
 - (क) परियोजना, परियोजना क्षेत्र तथा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमियों की सीमा का संक्षिप्त वर्णन।
 - (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण तथा सभी कार्यकलापों के उद्देश्य जो सामाजिक समाघात निर्धारण टीम द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।
 - (ग) परियोजना तथा भूमि अर्जन के आकार तथा जटिलता के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण कार्यवाही के लिए तिथि सहित परिदेय के लिए अनुक्रम, अनुसूची तथा अन्तिम तिथि तथा क्या ग्राम सभा तथा/या भू-स्वामियों की सहमति मांगी जानी अपेक्षित है।
 - (घ) विशिष्ट परियोजना के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण टीम का उपयुक्त आकार तथा रूपरेखा (क्षेत्रीय सर्वेक्षकों सहित, यदि आवश्यकता हो)।
 - (ङ) प्रत्येक मद या कार्यकलाप की लागतों के स्पष्ट विघटन सहित निर्देश-निबन्धन के आधार पर परियोजना-विशिष्ट बजट।
 - (च) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से परिभाषित परिदेयों से सहबद्ध सामाजिक समाघात निर्धारण टीम को निधियों के संवितरण की समय-सारणी।
- (iii) प्रक्रिया फीस प्रत्येक विशिष्ट परियोजना के निर्देश-निबन्धन तथा निर्धारित बजट के आधार पर अवधारित की जाएगी तथा परियोजना तथा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की किस्म, आकार, क्षेत्र तथा सुगृहिता (अति संवेदनशीलता) पर आधारित होगी। प्रक्रिया फीस की दरों तथा पृथक घटकों या लाइन मदों (आईटमस) की लागत के सम्बंध में सूचना सुसंगत होनी चाहिए तथा आसानी से अभिगम्य हो, ताकि अपेक्षक निकाय अग्रिम में इन्हें अपनी लागतों में कारक बना सके। इन दरों को समय-समय पर पुनरीक्षित तथा संशोधित करना चाहिए। फीस का एक नियत अंश सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई की लागतों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त होगा।

प्ररूप-III

(देखिए नियम 5(3), 9(5) तथा 9(6))

सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट**क सामाजिक समाधात निर्धारण में समाविष्ट सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक मापदण्डों की सूची**

- 1 परियोजना क्षेत्र में आबादी के जनसांख्यिकी ब्योरे ।
(क) आयु, लिंग, जाति, धर्म
(ख) साक्षरता, स्वास्थ्य तथा पोषणिक स्थिति
- 2 गरीबी स्तर
- 3 असुरक्षित समूह
(क) महिलाएं, (ख) बच्चे (ग) बुजुर्ग, (घ) महिला-प्रधान परिवार, (ङ) दिव्यांग
- 4 सगोत्रता पैटर्न तथा परिवार में महिलाओं की भूमिका
- 5 सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन
- 6 प्रशासकीय संगठन
- 7 राजनैतिक संगठन
- 8 सिविल सोसाइटी संगठन तथा सामाजिक गतिविधि
- 9 भूमि उपयोग तथा आजीविका :-
(क) कृषि तथा गैर-कृषि उपयोग
(ख) भूमि-मिट्टी, जल, वृक्षों इत्यादि की गुणवत्ता
(ग) पशुधन
(घ) औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्य तथा रोजगार
(ङ) श्रमिक के परिवार का विभाजन तथा महिलाओं के कार्य
(च) स्थानान्तरण (प्रवजन)
(छ) परिवार की आमदनी स्तर
(ज) आजीविका अभिरुचि (अधिमान)
(झ) खाद्य सुरक्षा
- 10 स्थानीय आर्थिक कार्यकलाप
(क) औपचारिक तथा अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग
(ख) ऋण सुलभता ।
(ग) मजदूरी दरें
(घ) विशिष्ट आजीविका कार्यकलाप जिनमें महिलाएं शामिल हैं ।
- 11 कारक जो स्थानीय आजीविकाओं में सहायक हैं ।
(क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच ।
(ख) सामूहिक सम्पत्ति संसाधन
(ग) निजी परिसम्पत्तियां
(घ) सड़के, परिवहन
(ङ) सिंचाई सुविधाएं
(च) बज़ार सुलभता
(छ) पर्यटक स्थल
(ज) आजीविका बढ़ाने के कार्यक्रम
(झ) सहकारी तथा अन्य आजीविका सम्बन्धी संघ
- 12 जीवन वातावरण गुणवत्ता
(क) ज्ञान, सौन्दर्यपरक गुणवत्तारूप, आसक्ति तथा आकांक्षाएं
(ख) पुनर्व्यवस्थापन पैटर्न
(ग) मकान
(घ) समुदाय तथा नागरिक स्थल
(ङ) धार्मिक तथा सांस्कृतिक साधनों के स्थल
(च) भौतिक अवसंरचना (जलआपूर्ति, मलजल प्रणाली इत्यादि सहित)
(छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी केन्द्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
(ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा
(झ) महिलाओं के लिए सामाजिक सभा बिन्दु

(ख) कुंजी समाघात क्षेत्र

- 1 भूमि, आजीविका तथा आमदनी समाघात
 - (क) रोजगार के स्तर तथा किस्म
 - (ख) अन्तर्परिवार रोजगार प्रतिकृति
 - (ग) आमदनी स्तर
 - (घ) खाद्य सुरक्षा
 - (ङ) जीवन स्तर
 - (च) उत्पादक संसाधनों तक पहुँच तथा नियन्त्रण
 - (छ) आर्थिक निर्भरता या असुरक्षा
 - (ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन
 - (झ) दरिद्रता जोखिम
 - (त्र) आजीविका विकल्प में महिलाओं की पहुँच
- 2 भौतिक संसाधनों पर समाघात
 - (क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वन पर समाघात
 - (ख) आजीविका के लिए भूमि तथा सामूहिक सम्पत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ।
- 3 निजी (प्राइवेट) परिसम्पत्तियां, लोक सेवाओं तथा उपयोगिताओं पर समाघात ।
 - (क) वर्तमान स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं की क्षमता
 - (ख) आवास सुविधाओं की क्षमता
 - (ग) स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति पर दबाव
 - (घ) विद्युत तथा जल आपूर्ति, सड़कें, सफाई तथा अपविष्ट प्रबन्धन प्रणाली की पर्याप्तता
 - (ङ) निजी (प्राइवेट) परिसम्पत्तियों जैसे कि नलकूप, अस्थाई शैड इत्यादि पर समाघात ।
- 4 स्वास्थ्य समाघात
 - (क) अन्तर प्रवसन के कारण स्वास्थ्य समाघात
 - (ख) निम्नलिखित पर विशेष महत्व सहित परियोजना कार्यक्रमों के कारण स्वास्थ्य समाघात :-
 - (i) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात
 - (ii) प्रौढ़ पर समाघात
- 5 संस्कृति तथा सामाजिक संसक्ति पर समाघात
 - (क) स्थानीय राजनैतिक संरचना का परिवर्तन
 - (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन
 - (ग) अर्थव्यवस्था परिस्थितिकी के संतुलन में बदलाव
 - (घ) मानकों, धारणाओं, मूल्यों तथा सांस्कृतिक जीवन पर समाघात
 - (ङ) अपराध तथा गैरकानूनी कार्यकलाप
 - (च) विस्थापन का दबाव
 - (छ) कुटुम्ब संसक्ति के पृथकरण का समाघात
 - (ज) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा ।
- 6 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर समाघात
 सामाजिक समाघात की किस्म, समय, अवधि तथा मात्रा, परियोजना चक्र के चरणों पर निर्भर तथा चरणों से निकट से सम्बद्ध होगी । नीचे समाघातों की निर्देशात्मक सूची है :-
 - (क) निर्माण पूर्व चरण
 - (i) सेवाओं को प्रदान करने में बाधा
 - (ii) उत्पादक निवेश में गिरावट
 - (iii) भूमि की अटकलबाजी
 - (iv) अस्थिरता का दबाव

(ख) निर्माण चरण

- (i) अपसरण विस्थापन और पुर्नअवस्थिति
- (ii) प्रवासी निर्माण कार्यबल अन्तर्वाह
- (iii) निर्माण स्थल के निकट निरन्तर रहने वालों पर स्वास्थ्य समाघात।

(ग) प्रचालन चरण

- (i) निर्माण चरण की तुलना में रोजगार अवसरों में कमी
- (ii) परियोजना के आर्थिक लाभ
- (iii) नई अवसंरचना के लाभ
- (iv) सामाजिक संगठन की नई प्रतिकृति

(घ) डी-कमीशनिंग चरण

- (i) आर्थिक अवसरों की हानि
- (ii) पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा आजीविका पर इसका समाघात

(ङ) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष समाघात

- (i) “प्रत्यक्ष समाघात” में सभी समाघात शामिल होंगे जो प्रभावित परिवारों को अनुभव होने सम्भाव्य हैं (अर्थात् प्रत्यक्ष भूमि तथा आजीविका खोनेवाले)
- (ii) “अप्रत्यक्ष समाघात” में सभी समाघात शामिल होंगे जो उन्हें अनुभव होंगे जो भूमि के अर्जन से प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं हुए हैं किन्तु जो परियोजना क्षेत्र में रह रहे हैं।

(च) विभेदक समाघात

- (i) महिलाओं, बच्चों, वयोवृद्ध तथा दिव्यांग पर समाघात
- (ii) लिंग समाघात निर्धारण, जांज सूची, मेघता तथा लोच आकलन आदि साधनों द्वारा चिन्हित समाघात

(छ) संचयी समाघात

- (i) प्रश्नगत परियोजना के परिलक्षित समाघातों सहित क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के परिमेय तथा सम्भाव्य समाघात
- (ii) उन पर समाघात जो परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं किन्तु स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से आधारित हैं।

अध्याय कार्यकारी सारांश।	(ग) सामाजिक समाघात रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात योजना की विषय सूची विषय (क) परियोजना तथा लोक प्रयोजन (ख) अवस्थान (ग) भूमि अर्जन का आकार तथा अवस्थिति (घ) विचारे गये विकल्प (ङ) सामाजिक समाघात (च) न्यूनीकरण उपाय (छ) सामाजिक लागतों का निर्धारण
विस्तृत परियोजना का उल्लेख।	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि जिसमें विकासक की पृष्ठभूमि तथा शासन या प्रबन्ध ढांचा शामिल है। (ख) परियोजना का मूलाधार जिसमें परियोजना अधिनियम में सूचीबद्ध मानदण्ड के अनुसार लोक प्रयोजन के लिए कैसे उचित है (ग) परियोजना आकार, अवस्थिति क्षमता, निर्गत, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिमों के ब्योरे (घ) विकल्पों का परीक्षण। (ङ) परियोजना निर्माण के चरण (च) बीजकोष डिजाईन आकृति तथा आकार तथा सुविधाओं की किस्म (छ) आनुषंगिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता (ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थायी तथा स्थायी) (झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के ब्योरे यदि पहले किया गया है तथा कोई तकनीकी सम्भाव्यता रिपोर्ट (ञ) लागू विधान तथा नीतियां।
सामाजिक समाघात निर्धारण टीम की संरचना, पहुंच, वर्गीकरण तथा अनुसूची।	(क) योग्यताओं सहित सभी टीम सदस्यों की सूची। टीम में शामिल किए जाने वाले लिंग विशेषज्ञ (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के वर्गीकरण तथा सूचना संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त साधनों का वर्णन तथा मूलाधार (ग) प्रयुक्त नमूना वर्गीकरण (घ) प्रयुक्त सूचना या डाटा का संक्षिप्त विवरण। विस्तृत सन्दर्भ प्रारूपों में पृथक रूप से शामिल करने होंगे (ङ) कुंजी हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची तथा आयोजित लोक सुनवाई का संक्षिप्त वर्णन या लोक सुनवाई तथा रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट पुनर्निवेशन प्रारूपों में शामिल करने होंगे
भूमि निर्धारण।	(क) भू-सम्पत्ति सूचियों तथा प्राथमिक स्रोतों से सूचना नक्शों की सहायता से वर्णन करें (ख) परियोजना के प्रभाव में समाघात का सम्पूर्ण क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित न हो) (ग) परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि (घ) परियोजना क्षेत्र के आस-पास में कोई लोक, उपयोग न की गई भूमि का वर्तमान उपयोग (ङ) पहले से ही खरीदी गई, हस्तांतरित, पट्टा या अर्जित भूमि (यदि कोई हो), तथा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट के लिए आशयित उपयोग (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा तथा अवस्थिति (छ) भूमि का स्वरूप, वर्तमान उपयोग तथा वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि, सिंचाई क्षेत्र तथा फसल चक्र (ज) जोत का आकार, स्वामित्व प्रतिकृति, भूमि वितरण, तथा आवासीय मकानों की संख्या (झ) पिछले तीन वर्षों में भूमि की कीमतें तथा स्वामित्व, अन्तरण और उपयोग में हुए नूतन परिवर्तन

<p>प्रभावित परिवारों तथा परिसम्पत्तियों का अनुमान तथा गणना (जहां अपेक्षित हो)।</p>	<p>परिवारों की निम्नलिखित किस्म का अनुमान निम्न अनुसार है:-</p> <p>(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित स्वामित्वाधीन भूमि जो (अर्जन के लिए प्रस्तावित है):</p> <p>(i) क्या अर्जित करने के लिए प्रस्तावित भूमि काश्तकार या अधिभोग में है;</p> <p>(ii) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी जिन्होंने अपने कोई वन अधिकार खो दिये हैं;</p> <p>(iii) सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों पर आजीविका के लिए निर्भर जो अर्जन के कारण प्रभावित होंगे;</p> <p>(iv) क्या सरकार द्वारा इसकी किसी स्कीम के अधीन भूमि दी गई है तथा ऐसी भूमि अर्जन के अधीन है;</p> <p>(v) भूमि के अर्जन से पूर्व पूर्ववर्ती तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए शहरी क्षेत्रों में किसी भूमि पर निवास किया है;</p> <p>(vi) क्या अर्जन से तीन वर्ष पूर्व आजीविका के प्रारम्भिक स्रोत के रूप में अर्जित करने वाली भूमि पर निर्भर रहे हैं।</p> <p>(ख) परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से समाघात हुआ है (अपनी भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुआ है)</p> <p>(ग) उत्पादक परिसम्पत्तियों और सार्थक भूमियों की सम्पत्ति-सूची।</p>
<p>सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपरेखा (प्रभावित क्षेत्र तथा पुनर्व्यवस्थापन स्थल)।</p>	<p>(क) परियोजना क्षेत्र में आबादी के जनसांख्यिकी ब्योरे;</p> <p>(ख) आमदनी तथा गरीबी स्तर;</p> <p>(ग) अतिसंवेदनशील समूह;</p> <p>(घ) भूमि उपयोग तथा आजीविका;</p> <p>(ङ) स्थानीय आर्थिक कार्यकलाप</p> <p>(च) कारक जो स्थानीय आजीविका में अंशदान करते हैं;</p> <p>(छ) संगोत्रता पैटर्न तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन;</p> <p>(ज) प्रशासकीय संगठन;</p> <p>(झ) राजनैतिक संगठन;</p> <p>(ञ) समुदाय आधारित तथा सिविल सोसाइटी संगठन;</p> <p>(ट) क्षेत्रीय गतिशील तथा ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रिया;</p> <p>(ठ) जीवन पर्यावरण की विशेषता।</p>
<p>सामाजिक समाघात।</p>	<p>(क) समाघात चिन्हित करने का ढांचा तथा तरीका;</p> <p>(ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघात का वर्णन जैसे कि स्वास्थ्य तथा आजीविका तथा संस्कृति पर समाघात। प्रत्येक किस्म के समाघात के लिए पृथक निर्देश चाहे ये प्रभावित परिवारों के विभिन्न प्रवर्गों पर तथा जहां संचयी समाघात लागू हों;</p> <p>(ग) भूमि, आजीविका तथा आमदनी, भौतिक संसाधनों, निजि परिसम्पत्ति, लोक सेवाओं में तथा उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा सामाजिक संसक्ति पर समाघात तथा लिंग आधारित समाघात सहित समाघात क्षेत्रों की निर्देश सूची।</p>
<p>अर्जन की लागतों तथा लाभों का विशलेषण तथा अर्जन की अनुशंसा।</p>	<p>(क) अन्तिम निष्कर्ष लोक प्रयोजन का निर्धारण, कम विस्थापन विकल्प, भूमि की न्यूनतम आवश्यकता, सामाजिक समाघातों की प्रकृति तथा तीव्रता, न्यूनीकरण उपायों की व्यवहार्यता तथा वह सीमा जिस तक सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना में वर्णित न्यूनीकरण उपाय, सामाजिक समाघातों और प्रतिकूल लागतों का उपाय करेंगे;</p> <p>(ख) उपरोक्त विशलेषण अन्तिम सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए विशलेषण के मापदण्ड के अनुसार निष्पक्षता सिद्धांत का प्रयोग करेगा कि क्या अर्जन को पूरा करना चाहिए या नहीं।</p>
<p>सन्दर्भ तथा प्ररूप।</p>	<p>सन्दर्भ तथा आगामी सूचना हेतु।</p>

(सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के अध्यक्ष तथा सदस्यों की मोहर तथा हस्ताक्षर)

प्ररूप-IV*[देखिए नियम 5(4)]***सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना**

1. न्यूनीकरण का तरीका (उपाय)
2. न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्ति समाघात के परिहार के उपाय।
3. उपाय जो अधिनियम में यथा प्रस्तुत पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन तथा प्रतिकर के रूप में शामिल हैं।
4. उपाय जो अपेक्षक निकाय ने परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तुत करने बारे कथन किया है।
5. अतिरिक्त उपाय जो अपेक्षक निकाय ने सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया तथा लोक सुनवाई के निष्कर्षों के जवाब में करने का कथन किया है।
6. सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना में संस्थागत ढांचों तथा प्रत्येक न्यूनीकरण उपाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा प्रत्येक गतिविधि की समयबद्धता तथा लागतों का विवरण शामिल होना चाहिए।

(सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के अध्यक्ष तथा सदस्यों की मोहर तथा हस्ताक्षर)

प्ररूप—V*[देखिए नियम 12(3) तथा अधिनियम की धारा 5]***लोक सुनवाई के लिए नोटिस**

संख्या:

दिनांक

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का कन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 5 के अधीन नोटिस दिया जाता है कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा गांव (गांवों).....
तहसील.....जिला.....में अवस्थित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन दिनांकको प्रकाशित अधिसूचना संख्या.....के अनुसार
के लिए आवश्यक है या आवश्यक के रूप में सम्भाव्य है। तदनुसार उक्त भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार के सम्बंध में लोक सुनवाई के लिए दिनांक.....को.....में.....के सम्मुख उपस्थित होने की अपेक्षित की जानी है।

अनुसूची

क्रम संख्या	खसरा संख्या	वर्णन	अपेक्षित सीमा (हेक्टेयर में)	भूमि के स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
-------------	-------------	-------	------------------------------	---

अध्यक्ष

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

<p style="text-align: center;">प्ररूप-VI <i>[देखिए नियम 17(3)]</i> भाग क पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप</p>				
क्रम संख्या	सम्बद्ध व्यक्ति के व्योरे			
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (i) तथा (v) के अनुसार व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम			
2.	पति/पत्नी का नाम			
3.	पिता/माता का नाम			
4.	पता			
5.	गांव/बस्ती			
6.	ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम			
7.	तहसील:			
8.	जिला:			
9.	आयु सहित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम (बच्चों तथा व्यस्क आश्रितों सहित)			
10.	स्वामित्वाधीन भूमि की सीमा			
11.	अर्जन के लिए क्षेत्र			
12.	प्लॉट संख्या			
13.	अधिकारों का अभिलेख			
14.	विवादित भूमि यदि कोई हो			
15.	पट्टा/पट्टे/अनुदान, यदि कोई हो			
16.	काश्तकारी सहित कोई अन्य अधिकार, यदि कोई हों			
17.	सरकार द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के बारे में, मैं निम्नलिखित कथित करना चाहता हूँ।			
	(i)	मैंने इस सहमति प्ररूप की विषय-वस्तु पढ़ ली है/पढ़वा ली है तथा..... भाषा में मुझे स्पष्ट कर दी गई है तथा।	हां	नहीं
	(ii)	मैं इस अर्जन से सहमत नहीं हूँ	हां	नहीं
	(iii)	मैं इस अर्जन से सहमत हूँ	हां	नहीं
प्रभावित परिवार (परिवारों) के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान और तिथि				

	अपेक्षक निकाय द्वारा वचनबद्ध निबन्धन तथा शर्तें, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर तथा अन्य उपायों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट कर दिया गया है (ये निबन्धन तथा शर्तें प्ररूप के साथ संलग्न की जाएंगी)
	हस्ताक्षरित प्ररूप प्राप्त करने वाले पदनामित जिला कर्मचारी की तिथि तथा हस्ताक्षर
18.	किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें कोई हानि पहुँचाना यदि वे सहमति देने से इनकार करते हैं या यदि वे यह करना पसन्द करते हैं कि वे इस प्ररूप पर सहमति नहीं देते, कानून के अधीन एक अपराध है। इसमें कोई धमकियां या कार्य शामिल हैं जो उन्हें कोई धन हानि करती हैं, जो उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुँचाता है या जो उनके परिवार में हानि पहुँचाता है। यदि कोई ऐसी धमकी इस रूप में की गई है, तो वह अकृत और शून्य है।

घोषणा

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथित सभी तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी, ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है तथा इसमें कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

मैंने इस सहमति प्ररूप की विषय-वस्तु को पढ़ लिया है इस सहमति प्ररूप की विषय-वस्तु मुझे पढ़ा दी गई है तथा सरल भाषा में मुझे स्पष्ट कर दी गई है तथा मैं मेरे स्वामित्व में उपरोक्त वर्णित भूमि के प्रस्तावित अर्जन के लिए अपनी सहमति देने के लिए सहमत हूँ/सहमत नहीं हूँ।

घोषणा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर

प्रभावित परिवार (परिवारों) के हस्ताक्षर

या अंगूठा निशान तथा तिथि :

कलक्टर या अधिकारों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रारूप—VII

[देखिए नियम 18(1)]

प्रारम्भिक अधिसूचना

संख्या.

दिनांक

चूंकि हरियाणा सरकार को यह प्रतीत होता है कि कुल.....एकड़ भूमि गांव..... तहसील.....जिला.....में लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्थात्.....सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा किया गया था तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2018 के नियम 9 में यथा अधिकथित कलक्टर द्वारा गठित अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/प्रारम्भिक अन्वेषण का संक्षिप्त-विवरण निम्न अनुसार है (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है):

भूमि अर्जन के कारण कुल.....(संख्या) परिवार विस्थापित किए जाने सम्भावित हैं। ऐसे विस्थापन की अनिवार्यता के कारण नीचे दिए गए हैं:-

.....कोप्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए गांव.....तहसील.....जिला.....मेंएकड़ भूमि का टुकड़ा अर्थात् मानक माप.....हेक्टेयर जिसके विस्तृत वर्णन निम्न अनुसार अर्जन के अधीन है:-

क्रम संख्या	खसरा संख्या	हक की किस्म	भूमि की किस्म	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता	सीमाएं			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
वृक्ष					ढांचा				
किस्म संख्या		किस्म कुर्सी क्षेत्र (वर्ग मीटर में)							

यह अधिसूचना, उन सभी के लिए जो इससे सम्बंधित हैं, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन की गई है।

भूमि का नक्शा कार्यालय समय के दौरान किसी कार्य दिवस को कलक्टर तथा.....के कार्यालय में निरीक्षित किया जा सकता है।

हरियाणा के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए भूमि में प्रवे 1 तथा सर्वेक्षण करने, किसी भूमि को समतल करने, अवमृदा को खोदने या बेचने तथा सभी अन्य अपेक्षित कार्य करने के लिए अधिकारी.....तथा उसके कर्मचारी.....को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन, कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ऐसी भूमि का अर्थात् विक्रय/क्रय इत्यादि हेतु कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा और कोई ऋण नहीं लेगा।

अर्जन के लिए आक्षेप, यदि कोई हो, कलक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 15 में यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

संलग्न: यथा उपरोक्त

स्थान:

दिनांक:

सचिव, सरकार

प्ररूप-VIII*[देखिए नियम 19(1) तथा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5)]*

कलक्टर द्वारा नोटिस

संख्या:.....

दिनांक:.....

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा गांवतहसील/अन्य नामावली..... जिला.....में अवस्थित भूमि हरियाणा राजपत्र दिनांकमें सरकार द्वारा प्रकाशित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपेक्षित है। तदनुसार भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त भूमि के अर्जन के लिए, यदि कोई हो, लिखित रूप में उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर.....के सम्मुख उनके आक्षेप दायर करने आवश्यक है।

कोई आक्षेप/कथन जो देय तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए हैं या जोमें भेजने वाले के हित के स्वरूप की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता है, तो भूमि सरसरी तौर पर अस्वीकृत करने के लिए दायी है।

देय तिथि में प्राप्त आक्षेप, यदि कोई हो.....में.....को उसकी जांच की जाएगी जब आक्षेपकर्ता व्यक्तिगत रूप में या वकील द्वारा पेश होने या अपने आक्षेपों के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेज सबूत प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	खसरा संख्या	कुल सीमा (एकड़ों में)	अर्जन के अधीन सीमा (एकड़ों में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता	सीमाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	वृक्षों, संरचनाओं इत्यादि के ब्योरे, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

स्थान:

दिनांक:

कलक्टर

प्ररूप-IX

(देखिए नियम 23)

भूमि अर्जन के कारण विस्थापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अधीन विकास योजना का प्रारूप

क्रम संख्या	दावाकर्ता/परिवार के मुखिया के नाम	स्थायी पता	पात्रताएं (देखिए अधिनियम की धारा 31, 41 तथा द्वितीय अनुसूचि)	टिप्पणी
			<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रति परिवार कृषि, बागवानी, पशु चरागाह क्षेत्र की भूमि के ब्योरे दिए जाएंगे। 2. प्रति परिवार निवास, आवास इकाई, पेयजल सुविधा शौचालय इत्यादि की व्यवस्था। 3. प्रति परिवार भारतीय रुपये में की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। 4. भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार मनरेगा या/तथा सरकार की कोई अन्य नौकरी देने वाली स्कीम के अधीन मुहैया कराया जाएगा। 5. प्रभावित परिवारों के युवाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से निपुणता विकास। 6. अवार्ड की तिथि से एक वर्ष के लिए भारतीय रुपये में..... प्रति मास के विस्थापित परिवार भत्ते के लिए निर्वाह अनुदान। 7. पशुबाड़े तथा छोटी दुकान के लिए न्यूनतम रुपए। 	

(क) देय भूमि अधिकार के ब्योरे, किन्तु जो निश्चित नहीं हुए हैं।

(ख) विशेष मुहिम चलाकर हस्तांतरित भूमि में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हकों को वापस करने की कार्यवाही के ब्योरे।

(ग) जनजातीय समुदायों तथा अनुसूचित जातियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर-वनभूमियों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा तथा गैर-काष्ठ वन उपज साधानों के विकास के लिए कार्यक्रम।

प्ररूप-X

[देखिए नियम 24]

घोषणा

संख्या.....

दिनांक.....

चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए गांव.....
तहसील.....जिला.....में कुलएकड़ भूमि अपेक्षित है,
अर्थात्.....

इसलिए घोषणा की जाती है कि गांवतहसील.....जिला.....में उपरोक्त परियोजना के
लिए अर्जन के अधीन.....एकड़ भूमि अर्थात् मानक माप कीहेक्टेयर का टुकड़ा जिसका विस्तृत
वर्णन निम्न अनुसार है:-

क्रम संख्या	खसरा संख्या	हक की किस्म	भूमि की किस्म	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता	सीमाएं			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
वृक्ष									
किस्म			संख्या						

ढांचा
किस्म कुर्सी क्षेत्र (वर्ग मीटर में)

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों की सुनवाई तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 15 में यथा उपबन्धित विधिवत जांच के बाद की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन किए जाने वाले सम्भावित परिवारों की संख्या.....है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान की गई है जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्न अनुसार है:-

गांव.....तहसील.....जिला.....क्षेत्र.....(एकड़ों में) भूमि का नक्शा किसी भी कार्य दिवस को भूमि अर्जन अधिकारी तथाके कार्यालय में निरीक्षित किया जा सकता है।

पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

सलग्न: यथा उपरोक्त

स्थान:

दिनांक:

सचिव, सरकार

प्ररूप—XI

[देखिए नियम 26]

भूमि अर्जन अवार्ड

भूमि अर्जन मामला संख्या

	परियोजना का नाम					
	घोषणा की संख्या तथा तिथि जिसके अधीन भूमि अर्जित की जानी है					
	भूमि की अवस्थिति एकड़ों में तथा सीमा, सर्वेक्षण नक्शे पर क्षेत्र प्लॉटों की संख्या, गांव जिसमें भूमि स्थित है, के साथ मील योजना की संख्या, यदि कोई हो।					
	भूमि का वर्णन अर्थात् क्या बंजर, जुती हुई, वास भूमि इत्यादि, यदि जुती हुई है, तो कितनी जुती हुई है, सिंचाई के स्रोत।					
	भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या तथा उनके सम्बंधित हितों का स्वरूप					
	वृक्षों, भवनों इत्यादि के बिना, यदि कोई हो, स्वतः भूमि के लिए अनुज्ञात राशि					
	भूमि हितबद्ध काश्तकार के प्रतिकर के रूप में ऐसी राशि में से अनुज्ञात राशि					
	संगणना का आधार					
	वृक्षों, गृह या किसी अन्य अचल सम्पत्ति के लिए अनुज्ञात राशि					
	फसलों के लिए अनुज्ञात राशि					
	धारा 30(3) के अधीन बाजार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर					
	धारा 28 के अधीन हानियां					
	धारा 30(1) के अधीन प्रतिकर					
	धारा 23 तथा 30 के अधीन अवार्ड					
	सरकारी राजस्व के उपशमन या भुगतान किए गए पूंजीगत मूल्य के ब्योरे, तिथि जिससे उपशमन प्रभावी होगा।					
	प्रतिकर की राशि का विभाजन	क्रम संख्या	दावाकर्ता का नाम	प्रत्येक को भुगतानयोग्य राशि	बैंक खाता	टिप्पणी
	क्षेत्र (एकड़ों में)					
	तिथि जिसको 2013 के अधिनियम 30 की धारा 38(1) के अधीन कब्जा लिया गया था।					

तिथि:

कलक्टर की मोहर तथा हस्ताक्षर

सभी मामलों में बैंक खातों के ब्योरे संगृहित किए जाने हैं जहां दावाकर्ता की आधार संख्या नहीं है या उसका आधार बैंक खाते से नहीं जोड़ा गया है।

1.	परियोजना का नाम							
2.	घोषणा की संख्या तथा तिथि जिसके अधीन भूमि अर्जित की जानी है							
3.	भूमि की अवस्थिति एकड़ों में तथा सीमा, सर्वेक्षण नक्शे पर क्षेत्र प्लाटों की संख्या, गांव जिसमें भूमि स्थित के साथ मील योजना की संख्या, यदि कोई हो।							
4.	अवास इकाई, परिवहन लागत, आवास भत्तों, वार्षिकी, रोजगार निर्वाह अनुदान, पशु बाड़े, छोटी दुकान, एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्तों का वर्णन							
5.	भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम तथा पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए उनके सम्बंधित दावे का स्वरूप							
6.	प्रतिकर की राशि का विभाजन क्षेत्र (एकड़ों में)	क्रम संख्या	दावाकर्ता / प्रभावित व्यक्ति का नाम	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन हकदारी	बैंक खाता संख्या	प्रत्येक का भुगतान योग्य राशि	नैर आर्थिक हकदारी	टिप्पणी
				(i) आवंटित किए जाने वाले मकान (ii) आवंटित की जाने वाली भूमि (iii) मत्स्य अधिकार (iv) वार्षिकी (v) रोजगार (vi) परिवहन लागत (vii) आवास भत्ते (viii) निर्वाह अनुदान (ix) पशु बाड़े, छोटे मकान (x) एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ते				
7.	तिथि जिसको पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन हकदारी प्रभावित परिवार को दी गई है							
8.	संगणना का आधार							
9.	वृक्षों, गृह या किसी अन्य अचल सम्पत्ति के लिए अनुज्ञात राशि							
10.	फसलों के लिए अनुज्ञात राशि							
11.	धारा 30(3) के अधीन बाज़ार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर							
12.	2013 के अधिनियम 30 की धारा 28 के अधीन हानियां							

13.	धारा 30(1) के अधीन प्रतिकर					
14.	धारा 23 तथा 30 के अधीन अवार्ड					
15.	सरकारी राजस्व के उपशमन का भुगतान किए गए पूंजीगत मूल्य के ब्योरे, तिथि जिससे उपशमन प्रभावी होगा।					
	प्रतिकर की राशि का विभाजन (क्षेत्र एकड़ों में)	क्रम संख्या	दावाकर्ता का नाम	प्रत्येक को भुगतान योग्य राशि	बैंक खाता	टिप्पणी
16.	तिथि जिसको 2013 के अधिनियम 30 की धारा 38(1) के अधीन कब्जा लिया गया था।					

तिथि:

कलक्टर की मोहर तथा हस्ताक्षर

सभी मामलों में बैंक खातों के ब्योरे संगृहित किए जाने हैं जहां दावाकर्ता की आधार संख्या नहीं है या उसका आधार बैंक खाते से नहीं जोड़ा गया है।

प्ररूप—XIII*[देखिए नियम 27 (3)]*

भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अधीन आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रारूप

क्रम संख्या	घटक	आधारभूत सुविधाएं
1.	सड़कें	
2.	जलनिकास	
3.	पेयजल	
4.	पशुओं के लिए पेयजल	
5.	चरागाह भूमि	
6.	उचित मूल्य की दुकानें	
7.	पंचायत भवन	
8.	डाकखाने	
9.	उर्वरक भण्डार	
10.	सिंचाई सुविधाएं	
11.	परिवहन सुविधाएं	
12.	कब्रिस्तान तथा शमशान घाट	
13.	प्रसाधन बिन्दु	
14.	विद्युत कनेक्शन	
15.	पौषणिक सेवाएं	
16.	विद्यालय	
17.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र	
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
19.	खेल मैदान	
20.	सामुदायिक केन्द्र	
21.	पूजास्थल	
22.	जनजातीय संस्थानों के लिए पृथक भूमि	
23.	इमारती लकड़ी वन उपज	
24.	सुरक्षा प्रबन्ध	
25.	पशुचिकित्सा सेवाएं	
26.	कोई अन्य आधारभूत सुविधाएं	

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 3rd January, 2018

No. S.O.-1/C.A. 30/2013/S. 109/2018.— In exercise of the powers conferred by section 109 read with section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013), and with reference to Haryana Government, Revenue & Disaster Management Department, notification No. S.O.-52/C.A.30/2013/S.109/2017, dated the 19th July, 2017, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:

CHAPTER I

General

- | | |
|---|---|
| Short title,
extent and
commencement. | <p>1. (1) These rules may be called the Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2018.</p> <p>(2) They shall extend to the whole of the State of Haryana.</p> <p>(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. \</p> |
| Defini-tions. | <p>2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) “Aadhaar authentication service” means electronic authentication carried out by Unique Identification Authority of India (UIDAI), or agencies appointed by it, after matching the biometric information of an individual at his request or with his consent, with the information maintained by UIDAI in its own central servers, and includes a ‘Yes/No’ response, or a response containing the demographic information and photograph of that individual;</p> <p>(b) “Aadhaar number” means a twelve digit unique identification number generated and issued to an individual by the Unique Identification Authority of India after de-duplication of demographic and biometric information pertaining to that individual;</p> <p>(c) “Act” means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013);</p> <p>(d) “Competent Authority” means the Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Revenue and Disaster Management Department;</p> <p>(e) “District Collector” means the Collector of the District or any other officer notified by the Government to perform the functions of District Collector;</p> <p>(f) “Expert Group” means the expert group constituted under sub-section (1) of section 7;</p> <p>(g) “Form” means the Form appended to these rules;</p> <p>(h) “Government” means the Government of the State Haryana in the Administrative Department concerned with the acquisition of land for the Requiring Body;</p> <p>(i) “published” means published,-</p> <p>(i) in the Official Gazette;</p> <p>(ii) in two daily newspapers having circulation in the area under acquisition, at least one of which shall be in local vernacular;</p> <p>(iii) by affixing the notification at conspicuous places in the affected areas in the Panchayat Ghar, Chaupals, Patwar Ghar, Dharamshalas, Community Center, the office of Municipality, Municipal Corporation, District Collector, Sub Divisional Officer (C) and the Tehsil, as the case may be. If the land is acquired on behalf of Haryana Urban Development Authority or any such other authority then the notification shall be affixed in their offices also;</p> |

- (iv) a proclamation shall be made by beat of drum followed by announcement to inform the general public; and
- (v) to be uploaded on the website of the Government:

Provided that the date of last publication by any of the mode as mentioned above, shall be considered for calculation of limitation, if any.

- (j) “section” means section of the Act.
- (k) “Social Impact Assessment” means the assessment made under section 4;
- (l) “Social Impact Management Plan” means a plan prepared as part of Social Impact Assessment process under sub-section (6) of section 4;
- (m) “Social Impact Assessment Unit” means a society, Corporation or any other body constituted by the Competent Authority or a unit accredited by the Government which is authorized to conduct Social Impact Assessment Study about any proposed acquisition;
- (n) “Urban area” means the area declared as Municipal area under clause (d) of article 243 p of the Constitution of India..

(2) words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Request for Land Acquisition

3. (1) Any requiring body or its representative duly authorized by it shall file the requisition to the concerned District Collector in **FORM-I** alongwith the following documents, namely:-

Requisition for acquisition of land..
section 4.

- (i) detailed project report;
- (ii) three copies of Record of Rights and revenue maps of the affected areas;
- (iii) information as available about the classification of land *i.e.*, irrigated multi-cropped, single cropped, wasteland, etc.;
- (iv) any other information required by the District Collector.

(2) Where the Requiring Body is the Government, the request shall be filed by the Secretary of the concerned Department or a person authorised by him.

4. (1) The District Collector, on receiving the requisition under sub-rule (1) of rule 3, shall constitute a committee consisting of officers from all the concerned departments involved, as he may deem necessary, to make a field visit along with the representatives of the Requiring Body to make a preliminary enquiry regarding –

Action by District Collector on receiving requisition
section 4

- (i) correctness of the particulars furnished in the request under sub-rule (1) of rule 3;
- (ii) bare minimum land required for the project;
- (iii) whether the request is consistent with the provisions of the Act, and submit a report to the District Collector.

(2) The report of the committee referred to in sub-rule (1) shall include its opinion on the following issues, namely:—

- (i) that the proposed acquisition of land serves public purpose;
- (ii) that the extent of land proposed for acquisition is the absolute bare-minimum needed for the project;
- (iii) that the acquisition of land at an alternate place has been considered and found not feasible;
- (iv) that there is no unutilised land suitable for the project which has been previously acquired in the area;

- (v) that the land, if any, acquired earlier and remained unutilised, may be used for such public purpose; and

(3) If the District Collector, on the basis of the report of the committee referred to in sub-rule (2), other information available with him and instructions issued by the Government in this regard, is satisfied that the requisition is consistent with the provisions of the Act, shall submit a report to the Government.

CHAPTER III

Social Impact Assessment

Social Impact
Assessment
study.
sections 4,5,6

5. (1) The Government after being satisfied with the report of the District Collector shall, publish a notification for initiating consultation with concerned local authority, in the affected area and for carrying out Social Impact Assessment study in accordance with **PART-A** of **FORM-II** of these rules:

Provided that such notification shall be published within thirty days of the deposit of the processing fee for carrying Social Impact Assessment by the Requiring Body, as determined under rule 7.

(2) The Social Impact Assessment shall be conducted in consultation with concerned local authority at village level or ward level in the affected areas, for the purposes of section 4, followed by a public hearing in the affected areas by giving adequate publicity about the date, time and venue for the public hearing, to ascertain the views of the affected families, which shall be duly recorded.

(3) The Social Impact Assessment Report shall be submitted in **FORM-III** to the Government within a period of six months from the date of its commencement and shall include the recorded views of the affected families.

(4) The Social Impact Management Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the project under sub-section (6) of section 4 shall also be submitted in **FORM-IV** along with the Social Impact Assessment Report.

(5) The Social Impact Assessment Report and the Social Impact Management Plan shall be published.

Institutional
support and
facilitation for
Social Impact
Assessment.
section 4.

6. The Social Impact Assessment Unit shall undertake the following tasks, namely:-

- (a) build and continuously expand a Database of Qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners, which shall serve as a network of individuals and institutions with the required skills and capacities to conduct Social Impact Assessments for land acquisition and Rehabilitation and Resettlement;
- (b) respond immediately to the Government's request for a Social Impact Assessment to be conducted by preparing a project-specific terms of reference;
- (c) conduct training and capacity building programmes for the Social Impact Assessment team and community surveyors and make available manuals, tools, comparative case study reports and other materials required for the analysis;
- (d) provide ongoing support and corrective action, as required during the Social Impact Assessment process;
- (e) ensure that the transaction based web-based workflow for Social Impact Assessments and Management Information System for land acquisition and rehabilitation and resettlement as specified in rule 22 is maintained and that all relevant documents are disclosed as per the provisions of the Act;
- (f) maintain, catalogue of all Social Impact Assessments and associated primary material; and
- (g) continuously review, evaluate and strengthen the quality of Social Impact Assessments and the capacities available to conduct them.

7. (1) Where the Government intends to acquire land, the proposal for such land acquisition shall be sent alongwith all the documents to the Social Impact Assessment Unit, which shall,-

Project-specific Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment.
section 4(5)

(a) prepare a detailed project-specific terms of reference for each proposal of land acquisition, listing all the activities that shall be carried out indicating the appropriate team size (and number of field teams) and profile of the team members, and stipulate the schedule and deadlines for key deliverables for the Social Impact Assessment as detailed in **PART-B** of **FORM-II** to these rules;

(b) determine an estimated Social Impact Assessment fee based on the terms of reference with clear break-up of costs for each item or activity. The fee amount shall be based on the parameters defined by the Government including area, type of project and number of affected families.

(2) Ten percent of the Social Impact Assessment fee shall be allocated to Social Impact Assessment Unit as administrative expenses for preparing the terms of references, Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan and submitting the same to the Government.

(3) The Requiring Body shall deposit in advance the Social Impact Assessment fee in the Scheduled Bank account of the concerned Social Impact Assessment Unit for the purpose.

8. (1) The Social Impact Assessment Unit shall be responsible for selecting the Social Impact Assessment team for each project from the individuals and institutions registered or empanelled in the Database of Qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners.

Selection of the Social Impact Assessment team.
section 4

(2) The Requiring Body shall not be involved in any way in the appointment of the Social Impact Assessment team being appointed to carry out the Social Impact Assessment.

(3) The size and selection criteria for the Social Impact Assessment team shall be as per the project specific terms of reference developed by the Social Impact Assessment Unit.

(4) The Social Impact Assessment team may be constituted by appointing individuals or an organization with experience in conducting Social Impact Assessments or related field-based assessments and the team may include,-

(a) a combination of independent practitioners, qualified social activists, academicians, technical experts, who are not directly connected with the Requiring Body; and

(b) at least one woman member.

(5) A team leader shall be appointed from amongst the members of the Social Impact Assessment team to liaison with the Social Impact Assessment Unit throughout the assessment period.

(6) While selecting the Social Impact Assessment team, it is to be ensured that there is no conflict of interest involving the team members appointed to assess the concerned project.

(7) All the members of Social Impact Assessment team shall give an undertaking by way of an affidavit mentioning that neither he nor any of his blood relations shall directly or indirectly receive any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project.

(8) If at any stage, it is found that any team member or any family member of the team member directly or indirectly receives any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project, the said member shall be disqualified, besides any other action against him which may be decided by the competent authority and shall not be included in any other Social Impact Assessment.

9. (1) The Social Impact Assessment team shall collect and analyze a range of quantitative and qualitative data, undertake detailed site visits, use participatory methods such as focused group discussions, participatory rural or urban appraisal techniques, as the case may be, and informant interviews in preparing the Social Impact Assessment report.

Process of conducting Social Impact Assessment.
section 4.

(2) All relevant project reports and feasibility studies shall be made available to the Social Impact Assessment team throughout the Social Impact Assessment process, as required. Any request for information from Social Impact Assessment team shall be met at the earliest but not exceeding ten days. The District Collector shall be responsible to provide the information requisitioned by the Social Impact Assessment team.

(3) A detailed assessment based on a thorough analysis of all relevant land records and data, field verification, review and comparison with similar projects shall be conducted by the Social Impact Assessment team. The assessment shall in addition to the matters provided under sub-section (4) of section 4, determine the following, namely:-

- (a) area of impact under the proposed project, including both land to be acquired and areas that shall be affected by environmental, social or other impacts of the project;
- (b) quantity and location of land proposed to be acquired for the project;
- (c) whether, the land proposed for acquisition in Scheduled Area is a demonstrable last resort;
- (d) land, if any, already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for every portion of land required for the project;
- (e) the possibility of use of any public, unutilized land for the project and whether any such land is under occupation;
- (f) nature of the land, present use and classification of land and if it is an agricultural land, the irrigation coverage for the said land and the cropping pattern;
- (g) whether the special provisions with respect to food security have been adhered to in the proposed land acquisition;
- (h) size of holdings, ownership patterns, land distribution, number of residential houses, and public and private infrastructure and assets; and
- (i) land prices and recent changes in matters of ownership, transfer and use of lands over the last three years.

(4) Based on the land assessment, land records and field verification, the Social Impact Assessment team shall provide an accurate estimate of the number of affected families and the number of displaced families among them and ensure that as far as possible all affected families are enumerated:

Provided that where enumeration is not possible, a representative sample shall be done by the Social Impact Assessment Unit.

(5) A socio-economic and cultural profile of the affected area shall be prepared, based on available data and statistics, field visits and consultations as per **FORM-III**.

Provided that in projects where resettlement is required, the identified resettlement sites shall be visited and a brief socio-economic profile of the land and its current resident population shall be indicated.

(6) Based on the data collected in processes listed above and in consultation with the affected communities and key stakeholders, the Social Impact Assessment unit shall identify and assess the nature, extent and intensity of the positive and negative social impacts associated with the proposed project and land acquisition as per **FORM-III**.

- (7) (i) The Social Impact Assessment process includes preparation of a Social Impact Management Plan, which shall present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified in the course of the assessment.
- (ii) The Social Impact Assessment team must assess the viability of impact mitigation and management strategies with clear indication of costs, timelines and capacities.

- (iii) The Social Impact Management Plan shall include the following measures, namely :-
- (a) that have been specified in the terms of rehabilitation and resettlement and compensation for all the categories of affected families, as outlined in the Act;
 - (b) that the Requiring Body has stated that it shall undertake in the project proposal and other relevant project documents; and
 - (c) the additional measures being undertaken by the Requiring Body in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

(8) The Social Impact Assessment team shall provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts and social costs and benefits of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceed the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement.

10. The final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be prepared in the local language and shall be forwarded to local authority, and the offices of the District Collector, Sub-Divisional Officer (C) and the Tehsildar and shall also be published.

Submission of Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

section 6

11. The Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be formulated keeping in view all the relevant information and analysis in a single document and reduced to writing that is clear, concise and accessible, in particular to the members of the affected families.

Social impact Assessment Report and Social impact Management Plan.

section 4(6)

12. (1) The public hearings shall be held in the affected areas to bring out the main findings of the Social Impact Assessment, seeking feedback on the findings and to seek additional information and views for incorporating the same in the final documents.

Process for conducting public hearings. section 5

(2) The public hearings shall be held in the affected area or as close to it as possible considering the ease of access, availability of resources, infrastructure etc. to conduct the public hearing. If the affected area encompasses more than one local authority, the public hearing shall be held in each of the local authorities within which land sought to be acquired is situated.

(3) The date, time and venue of the public hearing shall be published by the Social Impact Assessment unit at least three weeks prior to such date of hearing in form of notice in **FORM-V**.

(4) The draft Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan shall be published three weeks prior to the public hearing and distributed to all affected local authorities. One copy of the draft report shall be forwarded to the District Collector's office. The Requiring Body may also be served with a copy of the draft report. Adequate copies of the report and summaries shall be made available on the day of the public hearing. Accessible displays and other visual shall be used to share the findings of the Social Impact Assessment report.

(5) A member of the Social Impact Assessment team shall facilitate the public hearing which shall be organized through the local administration alongwith the Government officers *i.e.* Sub Divisional Officer (C)/Tehsildar, as may be specified. Public representatives in the local authorities shall also be included in all the decisions regarding the arrangements for the public hearings in their respective areas.

(6) All the proceedings shall be held in the local language with effective and credible translators, if needed, to ensure that all the participants may understand and express their views.

(7) Representatives from the Requiring Body and land acquisition and rehabilitation and resettlement functionaries such as Naib Tehsildar/Kanungos etc. dealing with the subject shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

(8) Public representatives, local voluntary organizations and media shall also be invited to attend the public hearings.

(9) The proceedings of the public hearing shall be video recorded and transcribed accordingly. This recording and transcription shall be submitted along with final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

(10) After the conclusion of the public hearings, the Social Impact Assessment team shall analyze the entire feedback received and information gathered in the public meetings and incorporate the same along with their analysis, in the revised Social Impact Assessment report accordingly.

(11) Every objection raised in the public meeting shall be recorded and the Social Impact Assessment team shall ensure that every objection is considered in the Social Impact Assessment report.

Appraisal of Social Impact Assessment report by an Expert Group. section 7

13. (1) The Expert Group shall evaluate the Social Impact Assessment report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

(2) The recommendations of the Expert Group shall be published.

Consideration of Social Impact Assessment Report, recommendations of Expert Group etc. section 7

14. (1) The Government shall examine the report of the District Collector, Social Impact Assessment report, the recommendations of the Expert Group, if any, and decide such area for acquisition which shall ensure minimum displacement of people, minimum disturbance to the infrastructure, ecology and minimum adverse impact on the individuals affected.

(2) The decision of the Government under sub-rule (1) shall be published.

CHAPTER IV

Consent

Consent of affected Land owners. section 2(2).

15. (1) In Public Private Partnership projects and projects by private companies, a list of all affected land owners from whom consent is required to be obtained, shall be drawn up by the District Collector in consultation with the Social Impact Assessment team. The list shall be published at least ten days prior to obtaining consent.

(2) In case of any objection, the views of the objector shall be considered and in case of rejection, the reasons for doing so shall be recorded in writing and conveyed to the concerned person within ten days.

(3) The District Collector shall in consultation with the representatives of local authorities, notify the date, time and venue at least three weeks in advance, for holding the affected land owners meetings at the village or ward level.

(4) The proposed terms and conditions agreed to by the Requiring Body shall also be made available in local language at least three weeks in advance of the meeting of the affected land owners, to each and every affected land owner.

(5) The Requiring Body or its representatives, who are competent to take decision and negotiate terms of rehabilitation and resettlement and compensation shall be present at all such affected land owners meetings and respond to the queries raised by the affected land owners. The terms and conditions of rehabilitation, resettlement and compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the members in the local language and signatures of the members as well as the representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) At the conclusion of the meeting, each individual land owner shall be asked to indicate in the signed declaration whether he gives or withholds consent for the acquisition of land involved. A copy of this declaration with the attached terms and conditions shall be given to the land owner concerned. The declaration shall be countersigned by the District Collector or any officer authorised by him in writing for this purpose.

(7) Those who could not attend the affected land owners meeting may submit their signed declarations to the District Collector within twenty one days from the date of land owners meeting. The declaration form shall be counter-signed by the District Collector or any officer authorised by him in writing for this purpose and a copy of the declaration, with the attached terms and conditions, shall be handed over to the affected landowner.

(8) All proceedings of taking affected land owners consent during land owners meetings shall be recorded in video and all the proceedings must be documented in writing.

(9) The outcome of the consent process shall be published.

(10) The members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist the affected land owners meeting.

(11) No land owner shall withdraw his consent once given in the aforesaid manner.

16. (1) The District Collector shall notify the date, time and venue of affected land owners meetings for obtaining the consent and organize public awareness campaigns to encourage participation of the affected land owners in the consent processes.

Roles and responsibilities of the Collector for consent processes. section 2 (2)

(2) The District Collector shall ensure that the following are provided in the local language at least three weeks in advance to every land owner from whom consent is sought, namely:—

- (a) a copy of the draft Social Impact Assessment report (if readily available) in the local language;
- (b) initial package being offered for compensation and rehabilitation and resettlement;
- (c) a list of the rights currently enjoyed by the village and its residents under Revenue Laws, Forest Rights Act and other legislations;
- (d) a written statement signed by the Collector, certifying that there shall be no consequences, if consent is denied for a project and stating that any attempt to coerce or intimidate in order to obtain consent, shall be illegal; and
- (e) contact details of the officer or authority along with official telephone number to be contacted in case of any attempt to coerce for signing the declaration of consent process.

(3) The District Collector shall attend the land owners meetings.

(4) The District Collector shall ensure that all the documents relating to Social Impact Assessment are made available to the affected land owners and any information sought is provided within seven days.

17. (1) The Requiring Body shall appoint representatives competent to take decisions and negotiate terms and conditions of compensation and rehabilitation and resettlement, who shall be present in the meetings of affected land owners for obtaining the consent and reply to the queries raised by the land owners.

Roles and responsibilities of the Requiring Body for consent processes. section 2

(2) The Requiring Body shall provide all the information on the project, prior to the taking of consent as well as any additional information, if required.

(3) The consent of affected land owners shall be obtained in **FORM-VI**.

CHAPTER-V

Preliminary Notification for Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Scheme

18. (1) After completion of the Social Impact Assessment Study and after obtaining consent of the affected families, whenever required, if it appears to the Government that land is required or likely to be required in any area for any public purpose, a preliminary notification referred to in section 11 shall be published in **FORM-VII**.

Publication of preliminary notification. Section 11

(2) After the preliminary notification is published under section 11, the Collector shall ensure completion of the exercise of updating land records as specified hereunder;-

- (a) delete the names of deceased persons;
- (b) enter the names of the legal heirs of the deceased persons;
- (c) take effect of the registered transactions of the rights in land such as sale, gift, partition, etc.;
- (d) make all entries of the mortgages in the land records;
- (e) delete the entries of mortgages in case the lending agency issues letter towards full payment of loans taken through registered re-conveyance of mortgaged property deeds;
- (f) make necessary entries in respect of all prevalent forest laws;
- (g) make necessary entries in case of the Government land and also in respect of land of local authorities;
- (h) make necessary entries in respect of assets on the land like construction, buildings, trees, wells, etc.;
- (i) make necessary entries of share-croppers in the land;
- (j) make necessary entries of crops grown or sown and the area of such crops; and
- (k) any other relevant entries.

Hearing of
objections.
Section 15

19. (1) The Collector after issuing notice in **FORM-VIII** and after hearing all objections and making enquiry as provided under sub-section (2) of section 15, shall submit a report under the said sub-section to the Government for its decision.

(2) The report of the Collector shall include the following namely:-

- (a) suitability assessment as to whether the proposed acquisition serves public purpose;
- (b) whether the extent of land proposed for acquisition is the absolute bare-minimum extent needed for the project;
- (c) suitability as to whether land acquisition at an alternate place has been considered and found not feasible;
- (d) there is no unutilised land which has been previously acquired in the area;
- (e) the land, if any, acquired earlier and remained unutilised, is used for such public purpose and recommendations in respect thereof;
- (f) suitability recommendations on the objections;
- (g) suitability record of proceedings;
- (h) suitability as to approximate cost of land acquisition ;
- (i) particulars as to number of affected families likely to be resettled.

Preparation of
Rehabilitation
and
Resettlement
Scheme and
public hearing.
section 16

20. (1) Upon publication of the preliminary notification under sub-section (1) of section 11, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement, shall conduct a survey and undertake a census of the affected families within a period of two months from the date of publication of such preliminary notification.

(2) For the purpose of the survey to be conducted and the census of the affected families to be undertaken by the Administrator, he shall in addition to factors as mentioned in sub-section (1) of section 16 of the Act, take into account –

- (a) the Social Impact Assessment report;

(b) the records of the local authorities, and other Government records.

(3) The Administrator shall get the data verified by door to door visit of the affected families and by site visits in case of infrastructure projects in the affected area.

(4) The draft Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by the Administrator shall, in addition to the particulars mentioned in sub-section (2) of section 16, contain the followings, namely:—

- (a) list of affected families, with Aadhaar number of its members, if available;
- (b) list of displaced families, with Aadhaar number of its members, if available;
- (c) list of infrastructure in the affected area;
- (d) list of land holdings in the affected area;
- (e) list of trees, buildings, other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired;
- (f) list of trades or businesses in the affected area;
- (g) list of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, divyangs in the affected area;
- (h) list of landless agricultural labourers in the affected areas;
- (i) list of unemployed youth in the affected families; and
- (j) time limit for implementing rehabilitation and resettlement Scheme:

Provided that in case a person does not have an Aadhaar number, efforts shall be made to get him so enrolled, provided he gives his consent for such enrolment and the claims of the affected families may be facilitated by carrying out consent-based Aadhaar authentication service.

(5) The Administrator shall prepare comprehensive and detailed draft Rehabilitation and Resettlement Scheme and publish the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme.

(6) The Administrator or an officer authorised by him shall conduct a public hearing in the affected areas by issuing advance notice of three weeks on the date, time and venue mentioned in the said notice in accordance with the provisions of rule 12 which shall, *mutatis mutandis*, apply to the public hearing in this case also.

21. After review of the Rehabilitation and Resettlement Scheme by the Collector as per provisions of sub section (1) of section 17 and approval of the scheme by the Commissioner as per provisions of sub section (2) of section 17 the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme shall be published by the Commissioner in the affected area and the Commissioner shall also inform the State Monitoring Committee constituted under section 50 about the publication of the approved Rehabilitation and Resettlement scheme.

Publication of approved Rehabilitation and Resettlement Scheme. section 18.

22. The Government shall create a dedicated, user-friendly website that may serve as a public platform on which the entire work flow of each acquisition case shall be hosted, beginning with the notification of the Social Impact Assessment and tracking each step of decision-making, implementation and audit.

Web-based Work Flow and Management Information system.

23. The Development Plan to be prepared in cases of a project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves, involuntary displacement of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes families, referred to in section 41 shall be as per **FORM IX**.

Development Plan for Scheduled Castes or Scheduled Tribes families. section 41.

CHAPTER VI

Declaration and Award

24. Upon receipt of a report of the Collector, as provided under sub-section (2) of section 15 and after examination and taking a decision on the objections, a declaration for acquisition of the land under sub-section (1) of section 19 alongwith the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme, shall be published by the Government in **Form-X**.

Publication of declaration for acquisition. section 19.

25. (1) The compensation shall be determined as per the provisions laid down under Section 26 to Section 30 read with the notification issued under column 3 against serial number 2 of the First Schedule to the Act.

Determination of compensation. section 26-30.

(2) The manner in which fishing rights shall be allowed to affected families in cases of irrigation or hydel projects under item 9 of Second Schedule of Act shall be notified by the Fisheries Department in consultation with Irrigation Department and Revenue Department or any other Department, as may be required.

(3) The payment of compensation shall be made through the account payee cheque/electronic mail transfer/Real Time Gross Settlement (RTGS) linked with Aadhar number.

(4) Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made in an award under sub-section (3) of section 33 and such person refuses to refund the said excess paid to him, then such amount shall be recovered as an arrear of land revenue.

Land acquisition
award.
section 23.

26. The Collector, after enquiry into and disposal of the objections, if any, raised by the interested persons in pursuance of the public notice published and given under sub-section (1) of section 21, shall make land acquisition award under section 23 of the Act as per **FORM-XI**.

Rehabilitation
and Resettlement
Award.
section 31, 37.

27. (1) The Collector shall also make Rehabilitation and Resettlement Award for each affected family in accordance with section 31 in **FORM-XII** and hand over family wise awards to each affected family.

(2) The recovery of any rehabilitation and resettlement benefit availed of by making a false claim or through fraudulent means, on refusal to refund shall be recovered as an arrear of land-revenue.

(3) The provision of infrastructural facilities and basic minimum amenities as specified in the Third Schedule of the Act are in **FORM-XIII**.

CHAPTER VII

Administration, Rehabilitation and Resettlement Committee and State Monitoring Committee

Powers, duties
and
responsibilities
of Administrator.
section 43.

28. The Sub Divisional Officer (C) or any officer not below the rank of extra Assistant Commissioner or any other officer of equivalent rank duly authorised by the Government in the State, shall act as Administrator for Rehabilitation and Resettlement. The Administrator shall have the following powers, duties and responsibilities, namely:-

- (a) to conduct a survey and undertake a census of the affected families and details of livestock possessed by each affected family in accordance with rule 20;
- (b) to prepare a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme (hereinafter referred to as the draft scheme);
- (c) to give wide publicity to the draft scheme in accordance with sub-rule (5) of rule 20 in the affected areas;
- (d) to make the draft scheme available to the concerned persons and authorities;
- (e) to organise and conduct public hearings on the draft Scheme;
- (f) to submit the draft scheme to the Collector;
- (g) to execute and monitor the rehabilitation and resettlement scheme;
- (h) to assist the Commissioner in post-implementation of social audit of rehabilitation and resettlement scheme; and
- (i) any other work required to be done for rehabilitation and resettlement.

Rehabilitation
and Resettlement
Committee at
Project Level.
(section 45).

29. (1) The Government shall constitute a Rehabilitation and Resettlement Committee at project level to monitor and review the progress and implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme and to carry out post-implementation social audits in consultation with the Gram Sabha in the rural area and Municipality, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be, in the urban area.

(2) The Committee shall have its first meeting when a draft scheme has been prepared by the Administrator. The Committee shall discuss the draft scheme and make suggestions and recommendations. Thereafter, the Committee shall meet to review and monitor the progress of rehabilitation and resettlement once in a month till the process of rehabilitation and resettlement is completed;

(3) For the purpose of carrying out the post-implementation social audits, the Committee shall meet once in three months;

(4) The Committee may visit the affected area and discuss with the affected families, if it so desires and also visit the resettlement area to monitor the resettlement process.

(5) The Member-Convener of the Committee shall be assisted by subordinate officers and staff provided by the Government.

(6) The members of the Committee shall get travelling and daily allowance at the rate admissible to the Class I Officers of the Government and amount shall be paid by District Collector from the fund provided for these purposes by the Requiring Body.

30. (1) The State Monitoring Committee, shall review and monitor the implementation of the Rehabilitation and Resettlement Schemes for the projects within two months of the publication of the approved schemes by the Commissioner under section 18 and thereafter, the meetings of the Committee shall be held once in three months to review and monitor the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes.

Procedure of
State Monitoring
Committee.
section 50(3)

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Committee may –

- (a) call for records and information of rehabilitation and resettlement schemes;
- (b) call the Requiring Body for discussion as and when required;
- (c) ask for report about implementation of its decision from Rehabilitation and Resettlement Committee.

(3) The non-official experts associated with the State Monitoring Committee, shall be paid travelling and daily allowance at the rate admissible to an officer of the rank of Secretary in the Government.

CHAPTER VIII

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority

31. The salaries, allowances and conditions of service of the Presiding Officer and Registrar and other officers and staffs of the Authority, shall be specified separately by the Government after due consultation with the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court.

Salaries,
allowances, etc.
of Presiding
Officer, Registrar
and other officers
and employees of
Authority.
section 56

32. (1) If the Collector after inquiry comes to the conclusion that a person has wrongly been given compensation because of the claim based on fraud, misrepresentation or adopting illegal means etc., the Collector shall make a reference to the Authority for taking action against the erring person and the said action shall be without prejudice to the action which can be taken under any other law for the time being in force.

Power of
Authority and
Recovery of
Rehabilitation
and Resettlement
benefits availed
through false
claim etc.

(2) The land and houses so vacated shall be used for the Rehabilitation and Resettlement of the affected persons by the same project or for the purpose of community, as the case may be.

section 60 & 84

Miscellaneous

33. The limits on extent of land beyond which provisions of which Rehabilitation and Resettlement under the Act in cases of purchase by a private company through Private Negotiation for public purpose with the owner of the land shall be as specified by the Government from time to time.

Limits on extent
of land.
section 2(3)(a)

34. (1) When any land acquired under the Act remains unutilised for a period of five years, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank of the Government by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing necessary order in writing by the Divisional Commissioner in this behalf for this purpose, as per terms and conditions decided by the Government from time to time.

Manner of return
of unutilized land.
(section 101)

(2) After passing the order by Divisional Commissioner under sub-rule (1), the District Collector shall take the possession of the acquired land for the purpose of returning the same to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank of the Government and order for making any entries in this regard in the relevant record.

(3) If the Requiring Body does not handover possession of the said land to the District Collector, the District Collector shall be competent to take the help of the concerned Executive Magistrate and police force to take the possession by giving prior notice to the Requiring Body.

Repeal

35. The Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014 shall stand repealed:

Provided that any action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been taken under these rules.

FORM-I*[(See rule-3(1))]***Request for Acquisition of Land**

From:

Name

and/or Designation of the Requiring Body

To:

1. The District Collector _____
2. Commissioner, R&R, _____

It is requested to acquire _____ acre(s) of land for _____ project/purpose and the details are furnished in Annexure (Annexures) I, II & III alongwith three copies of Combined Sketch (to scale) showing the lands to be acquired. The gestation period of the project will be _____ years and _____ months (applicable only if gestation period is more than 5 years).

Requisite cost of acquisition including cost of social impact assessment study (SIA) is available and shall be deposited in your office, as provided under provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 as and when required by you. It is certified that the land to be acquired was demarcated on the field and all further necessary information and assistance shall be provided on the date/time appointed/stipulated by you.

Yours faithfully

Requiring Body

Annexure-I**Name of the project:-**

- (1) Name of the village-
- (2) Name of the Tehsil-
- (3) Name of the Municipality/Municipal Corporation-
- (4) Name of the District-
- (5) Khasra Nos. to be acquired-
- (6) Total area under request (in acres)-
- (7) Boundaries of the area to be acquired-
East-
West-
North-
South-
- (8) Area of the agricultural and irrigated multi-cropped land (mentioned separately)
- (9) Reasons for inclusion of agricultural and irrigated multi-cropped land _____
- (10) Details of buildings and other structures, tanks, wells, tress, etc.,
- (11) Reasons for the inclusion of religious building, graveyard or tomb etc. for acquisition, if any.

Requiring Body

Annexure-II**Name of the project:-**

1. Department or Government or Company, Local Authority, Institution:
2. Official designation of the requiring body:-
3. Purpose of Acquisition (in detail):-
4. Whether the request is filed u/s 2(1) of the Act by the Government or Department for its own use hold and control:-
5. Whether the request is filed u/s 2(1) (a) to 2(1) (f) of the Act:-
6. Whether the request is filed u/s 2(2) (a) or (b) of the Act:-
7. How many families are affected as described u/s 3 (c) (i) to (vi) of the Act:-
8. Whether the request is filed under Section 40 of the Act:-
9. If so, on what ground ?
10. Has the land for the project been partially purchased from the owners by private negotiation?
11. If so, on what date and on what terms (please state the terms of negotiation in short and attach the copy of it)
12. Date of issue of administrative approval for the project (copy to be attached) in case of Government or department or local authority.
13. Reasons for delay in filing request, if request is filed after six weeks from the date of administrative approval of the project in case of Government or Department or local authority.
14. By what time possession of the land is required.

Requiring Body

Annexure-III

Certificate to be furnished along with the request for acquisition of land by the requiring authorities.

Name of the project:-

- (1) Certified that the project for which the land is sought to be acquired has been administratively approved vide Department letter No. _____ dated _____ for acquisition under the Act (Copy of letter attached).
- (2) The estimated cost of the project is of INR _____ and necessary budget was sanctioned and funds are available towards cost of acquisition.
- (3) The Department undertakes to pay the full amount in case of decree by the Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority/High Court/Supreme Court as and when asked to do so by the Collector.

Requiring Body

FORM-II

[For Part-A, see rule-5(1) and for Part-B, see rule 7(1)]

Part-A. Notification of the Social Impact Assessment

No.

Chandigarh., Dated

Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified in the Schedule below is needed or likely to be needed for a public purpose, namely,

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, (Central Act 30 of 2013) the Governor of Haryana has decided to conduct a Social Impact Assessment in the area specified in the schedule below;

Now therefore, sanction is accorded to the a Social Impact Assessment Unit, District to conduct a Social Impact Assessment Study and to prepare a Social Impact Management Plan as provided in the Act. The process shall be completed within a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE OF THE AREA

District:

Tehsil:

Village

(The extent given is approximate)

Extent of Land (in acres)

Secretary to Government.

Part -B. Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact

- (i) The Social Impact Assessment Unit shall review the proposal for land acquisition sent by the Government and produce a project-specific Terms of Reference and budget. Based on the Terms of Reference and budget, a processing fee shall be determined, which shall be deposited by the Requiring Body before the notification of the Social Impact Assessment is issued.
- (ii) The Terms of Reference shall include the following information:-
 - (a) a brief description of the project, project area and the extent of lands proposed for acquisition.
 - (b) the objectives of the Social Impact Assessment and all the activities that shall be carried out by the Social Impact Assessment team.
 - (c) sequencing, schedule and deadlines for deliverables with dates for the Social Impact Assessment process, based on the size and complexity of the project and land acquisition, and whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required to be sought.
 - (d) the appropriate size and profile of the Social Impact Assessment team required (including field surveyors, if needed) to conduct the Social Impact Assessment for the specific project.
 - (e) a project-specific budget based on the Terms of Reference, with a clear break-up of costs for each item or activity.
 - (f) the schedule for the disbursement of funds to the Social Impact Assessment team tied to clearly defined deliverables in the Social Impact Assessment process.
- (iii) The processing fee shall be determined based on the Terms of Reference and budget developed for each specific project and shall be based on the type, size, location, and sensitivity of the project and the land proposed for acquisition. Information regarding the processing fee bands and the cost for separate components or line items shall be made consistent and easily accessible, so that the Requiring Body can factor this into its costs in advance. These rates shall be reviewed and revised from time to time. A fixed proportion of the fee shall go towards meeting the costs of the Social Impact Assessment Unit.

FORM-III*[See rules-5(3), 9(5) and 9 (6)]***Social Impact Assessment Report****A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the Social Impact Assessment**

1. Demographic details of the population in the project area
 - (a) Age, sex, caste, religion
 - (b) Literacy, health and nutritional status
2. Poverty levels
3. Vulnerable groups
 - (a) Women, (b) children, (c) the elderly, (d) women-headed households, (e) the differently abled
4. Kinship patterns and women's role in the family
5. Social and cultural organisation
6. Administrative organisation
7. Political organisation
8. Civil society organisations and social movements
9. Land use and livelihood
 - (a) Agricultural and non-agricultural use
 - (b) Quality of land – soil, water, trees etc.
 - (c) Livestock
 - (d) Formal and informal work and employment
 - (e) Household division of labour and women's work
 - (f) Migration
 - (g) Household income levels
 - (h) Livelihood preferences
 - (i) Food security
10. Local economic activities
 - (a) Formal and informal, local industries
 - (b) Access to credit
 - (c) Wage rates
 - (d) Specific livelihood activities women are involved in
11. Factors that contribute to local livelihoods
 - (a) Access to natural resources
 - (b) Common property resources
 - (c) Private assets
 - (d) Roads, transportation
 - (e) Irrigation facilities
 - (f) Access to markets
 - (g) Tourist sites
 - (h) Livelihood promotion programmes
 - (i) Co-operatives and other livelihood-related associations

12. Quality of the living environment
 - (a) Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations
 - (b) Settlement patterns
 - (c) Houses
 - (d) Community and civic spaces
 - (e) Sites of religious and cultural meaning
 - (f) Physical infrastructure (including water supply, sewage systems etc.)
 - (g) Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)
 - (h) Safety, crime, violence
 - (i) Social gathering points for women

B. Key impact areas

1. Impacts on land, livelihoods and income
 - (a) Level and type of employment
 - (b) Intra-household employment patterns
 - (c) Income levels
 - (d) Food security
 - (e) Standard of living
 - (f) Access and control over productive resources
 - (g) Economic dependency or vulnerability
 - (h) Disruption of local economy
 - (i) Impoverishment risks
 - (j) Women's access to livelihood alternatives
2. Impacts on physical resources
 - (a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
 - (b) Pressures on land and common property natural resources for livelihoods
3. Impacts on private assets, public services and utilities
 - (a) Capacity of existing health and education facilities
 - (b) Capacity of housing facilities
 - (c) Pressure on supply of local services
 - (d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system
 - (e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.
4. Health impacts
 - (a) Health impacts due to in-migration
 - (b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:-
 - (i) Impact on women's health
 - (ii) Impact on the elderly
5. Impacts on culture and social cohesion
 - (a) Transformation of local political structures

-
- (b) Demographic changes
 - (c) Shifts in the economy-ecology balance
 - (d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life
 - (e) Crime and illicit activities
 - (f) Stress of dislocation
 - (g) Impact of separation of family cohesion
 - (h) Violence against women
6. Impacts at different stages of the project cycle
- The type, timing, duration, and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts
- (a) Pre-construction phase
 - (i) Interruption in the delivery of services
 - (ii) Drop in productive investment
 - (iii) Land speculation
 - (iv) Stress of uncertainty
 - (b) Construction phase
 - (i) Displacement and relocation
 - (ii) Influx of migrant construction workforce
 - (iii) Health impacts on those who continue to live close to the construction site
 - (c) Operation phase
 - (i) Reduction in employment opportunities compared to the construction phase
 - (ii) Economic benefits of the project
 - (iii) Benefits on new infrastructure
 - (iv) New patterns of social organisation
 - (d) De-commissioning phase
 - (i) Loss of economic opportunities
 - (ii) Environmental degradation and its impact on livelihoods
 - (e) Direct and indirect impacts
 - (i) “Direct impacts” shall include all impacts that are likely to be experienced by the *affected families (i.e. Direct land and livelihood losers)*
 - (ii) “Indirect impacts” shall include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area
 - (f) Differential impacts
 - (i) Impact on women, children, the elderly and the different abled
 - (ii) Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping
 - (g) Cumulative impacts
 - (i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question.
 - (ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

C. Table of Contents for Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan

Chapter	Contents
Executive Summary	<ul style="list-style-type: none"> (a) Project and public purpose (b) Location (c) Size and attributes of land acquisition (d) Alternatives considered (e) Social Impacts (f) Mitigation measures (g) Assessment of social costs.
Detailed Project Description	<ul style="list-style-type: none"> (a) Background of the project, including developers background and governance or management structure (b) Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria listed in the Act. (c) Details of project size, location, capacity, outputs, production targets, cost, risks (d) Examination of alternatives (e) Phases of project construction (f) Core design features and size and type of facilities (g) Need for ancillary infrastructural facilities (h) Work force requirements (temporary and permanent) (i) Details of Social Impact Assessment or Environmental Impact Assessment if already conducted and any technical feasibility reports (j) Applicable legislations and policies
Team composition, approach, methodology and Schedule of the Social Impact Assessment	<ul style="list-style-type: none"> (a) List of all team members with qualifications. Gender experts to be included in team. (b) Description and rationale for the methodology and tools used to collect information for the Social Impact Assessment. (c) Sampling methodology used. (d) Overview of information or data sources used. Detailed reference must be included separately in the forms. (e) Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public hearings conducted. Details of the public hearings and the specific feedback incorporated into the Report must be included in the forms.
Land Assessment	<ul style="list-style-type: none"> (a) Information from land inventories and primary sources - Describe with the help of the maps (b) Entire area of impact under the influence of the project (not limited to land area for acquisition) (c) Total land requirement for the project (d) Present use of any public, unutilised land in the vicinity of the project area (e) Land (if any) already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project (f) Quantity and location of land proposed to be acquired for the project (g) Nature, present use and classification of land and if agricultural land, irrigation coverage and cropping patterns (h) Size of holdings, ownership patterns, land distribution, and number of residential houses (i) Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last 3 years.

Estimation and enumeration (where required) of affected families and assets	<p>Estimation of the following type of families that are-</p> <p>(a) Directly affected (own land that is proposed to be acquired):</p> <p>(i) Are tenants or occupy the land proposed to be acquired</p> <p>(ii) The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights</p> <p>(iii) Depend on common property resources which will be affected due to acquisition of land for their livelihood</p> <p>(iv) Have been assigned land by the Government under any of its schemes and such land is under acquisition;</p> <p>(v) Have been residing on any land in the urban areas for preceding three years or more prior to the acquisition of the land</p> <p>(vi) Have depended on the land being acquired as a primary source of livelihood for three years prior to the acquisition</p> <p>(b) Indirectly impacted by the project (not affected directly by the acquisition of own lands)</p> <p>(c) Inventory of productive assets and significant lands</p>
Socio-economic and cultural profile (affected area and resettlement site)	<p>(a) Demographic details of the population in the project area</p> <p>(b) Income and poverty levels</p> <p>(c) Vulnerable groups</p> <p>(d) Land use and livelihood</p> <p>(e) Local economic activities</p> <p>(f) Factors that contribute to local livelihoods</p> <p>(g) Kinship patterns and social and cultural organisation</p> <p>(h) Administrative organisation</p> <p>(i) Political organisation</p> <p>(j) Community-based and civil society organisations</p> <p>(k) Regional dynamics and historical change processes</p> <p>(l) Quality of the living environment</p>
Social impacts	<p>(a) Framework and approach to identifying impacts</p> <p>(b) Description of impacts at various stages of the project cycle such as impacts on health and livelihoods and culture. For each type of impact, separate indication of whether it is a direct or indirect impact, differential impacts on different categories of affected families and where applicable cumulative impacts</p> <p>(c) Indicative list of impacts areas include: impacts on land, livelihoods and income, physical resources, private assets, public services and utilities, health, culture and social cohesion and gender based impacts</p>
Analysis of costs and benefits and recommendation on acquisition	<p>(a) Final conclusions on: assessment of public purpose, less-displacing alternatives, minimum requirements of land, the nature and intensity of social impacts, the viability of the mitigation measures and the extent to which mitigation measures described in the Social Impact Management Plan will address the full range of social impacts and adverse social costs.</p> <p>(b) The above analysis will use the equity principle as a criteria of analysis for presenting a final recommendation on whether the acquisition should go through or not</p>
References and Forms	For reference and further information

(Seal and signature of the Chairman and Members, Social Impact Assessment Unit.)

FORM-IV*[See rule-5 (4)]***Social Impact Management Plan**

1. Approach to mitigation
2. Measures to avoid, mitigate and compensate impact
3. Measures that are included in the terms of Rehabilitation & Resettlement and compensation as outlined in the Act
4. Measures that the Requiring Body has stated it shall introduce in the Project Proposal
5. Additional measures that the Requiring Body has stated it shall undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings
6. The Social Impact Management Plan must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity.

*(Seal and signature of the Chairman and Members,
Social Impact Assessment Unit.)*

FORM- V*[See rule- 12 (3) and section 5 of the Act]***NOTICE FOR PUBLIC HEARING**

No.

Dated:

Notice under section 5 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013) is hereby given that the land specified in the appended schedule and situated in village (s), Tehsil of District is needed or likely to be needed for a public purpose, namely, in accordance with the notification No. published on, under sub-section (1) of section 4 of the said Act. All persons interested in the said land are accordingly required to appear before the on at for a public hearing in connection with the preparation of Social Impact Assessment Report.

SCHEDULE

Serial No.	Khasra No.	Description	Extent required in hectares	Name of Owners of Land/Interested
------------	------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------------

*Chairman**Social Impact Assessment Unit.*

FORM-VI*[See rule-17(3)]***PRIOR WRITTEN CONSENT / DECLARATION FORM**

Sr. No.	Detail of person Concerned	
1	Name of the person(s) as per section 3(c) (i) and (v) of the Act	
2	Name of the spouse	
3	Name of father/ mother	
4	Address	
5	Village / Basti	
6	Gram Panchayat / Municipality / Municipal Corporation	
7	Tehsil:	
8	District:	
9	Name of other members in the family with age: (including children and adult dependents)	
10	Extent of land owned	
11	Area for the acquisition	
12	Plot No	
13	Record of Rights	
14	Disputed lands if any	
15	Pattas/ leases/ grants, if any	
16	Any other right, including tenancy, if any:	
17	Regarding the acquisition of my land by the government, I wish to state the following (please circle)	
	(i) I have read/readout the contents of this consent form and explained to me in _____ language and	Yes No
	(ii) I do not agree to this acquisition	Yes No
	(iii) I agree to this acquisition	Yes No
	Signature or Thumb impression of the affected family(s) and date:	

18	The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation and other measures committed by the Requiring Body have been explained in the local language. (These terms and conditions must be attached to the Form).
	Date and Signature of designated district official receiving the signed form
	It is a crime under law to threaten any person or to cause them any harm if they refuse to consent or if they choose to state that they do not consent on this form. This includes any threat or act that causes them to lose money, that hurts them physically or that results in harm to their family. If any such threat has been made this form is null and void.

Declaration

I hereby declare that all the facts stated above are true and correct to the best of my information, knowledge and belief and no material has been concealed there from.

I have read the contents of this consent form/the contents of this consent form have been read out to me and explained to me in language and I agree/do not agree to give my consent to the proposed acquisition of the land described above in my ownership.

Signature of the person(s) giving the declaration:

Signature or Thumb impression of the affected family(s) and date:

Countersigned by: *The Collector or the Officer*

FORM-VII*[See rule-18(1)]***PRELIMINARY NOTIFICATION**

No. _____

Dated: _____

Whereas, it appears to the Governor of Haryana that a total of _____ acres land is required in the _____ Village _____ Tehsil _____ District for public purpose, namely, _____ Social Impact Assessment Study was carried out by Social Impact Assessment Unit and a report submitted/preliminary investigation was conducted by a team of officers constituted by the Collector as laid down under rule 9 of the Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2018. The summary of the Social Impact Assessment report/preliminary investigation is as follows (Attach copy of SIA report):

A total _____ (no.) families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is given below.

_____ is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore, it is notified that for the above said project in the _____ village of _____ Tehsil _____ District a piece of land measuring, _____ acres viz, _____ hectare of standard measuring, whose detail description is as following, is under acquisition:

Serial Number	Khasra No.	Type of Title	Type of Land	Area under Acquisition (in acre)	Name and Address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.

Tress	
Variety	Number

Structures	
Type	Plinth area (in sq m)

This notification is made under the provisions of sub-section (i) of section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013), to all to whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector and _____ on any working day during the working hours.

The Governor of Haryana hereby authorizes Officers _____ and his staff _____ to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil & do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within a period of sixty days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Collector.

Encl: As above

Place:

Date:

Secretary to the Government

FORM-VIII*[See rule-19 (1) and sub section (2) of section 15 of the Act]***NOTICE BY COLLECTOR**

No. _____

Dt. _____

Notice is hereby given that the land specified in the appended schedule and situated in the village of _____ in the Tehsil/other nomenclature _____ in the District of _____ is needed in accordance with the notification under sub-section (i) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013) published by the Government in Official Gazette dated _____. All persons interested in the land are accordingly required to lodge their objections before _____

_____ within a period of sixty days from the date of publication of the above notification in writing, if any, to the acquisition of the said land. Any objection statement which is received after the due date or which does not clearly explain the nature of the senders interest in the lands is liable to be summarily rejected.

Objections received within the due date, if any, shall be enquired into on _____ at _____ when the objectors shall be at liberty to appear in person or by Advocate and to adduce any oral or documentary evidence in support of their objections.

SCHEDULE

Serial Number	Khasra No.	Total extent (in acres)	Extent under acquisition (in acres)	Name and address of the person interested	Boundaries N.S.E.W.	Details of Trees, Structures etc., if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Place:

Date:

Collector

FORM-IX*[See rule-23]*

Format for Development Plan under Rehabilitation and Resettlement scheme for SC/ST families displaced due to land acquisition

Serial Number	Name of the Claimant/family head	Permanent Address	Entitlements (See section 31,41 and Second Schedule of the Act)	Remarks
			<p>1. Particulars of land for agricultural, horticultural, cattle grazing field per family shall be provided.</p> <p>2. Provision of dwelling housing unit per family, Drinking Water facility toilette etc.,</p> <p>3. One time financial assistance of INR per family shall be given.</p> <p>4. For landless laborers employment shall be provided under MNREGA or/and any other job providing scheme of the government.</p> <p>5. Skill development through different training programs for the youth of affected family.</p> <p>6. Subsistence grant for displaced family allowance equivalent to INR per month for a year from the date of award.</p> <p>7. For cattle shed and petty shop minimum Rupees</p>	

- (a) Details of Land right due, but not settled:
- (b) Details of actions for restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive.
- (c) Programme for development of alternate fuel, fodder and non-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes.

FORM-X*[See rule-24]***DECLARATION**

No. _____ The _____

Whereas, it appears to the Governor of Haryana that a total of _____ acres land is required in the Village _____ Tehsil _____ District _____ for public purpose, namely, _____.

Therefore declaration is made that a piece of land measuring _____ acres viz; _____ hectares of standard measurement under acquisition for the above said project in the Village _____ Tehsil _____ District _____ whose detailed description is as following:-

Sr. No.	Khasra No.	Type of title	Type of Land	Area under Acquisition (in acres)	Name and Address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.

Trees	
Variety	Number

Structures	
Type	Plinth area (in sq m)

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided under section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to Land Acquisition is _____ for whom Resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village _____ Tehsil _____ District _____ Area _____ (in acres).

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer and _____ on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl: As above

Place:

Date:

Secretary to the Government

FORM-XI*[See rule-26]***LAND ACQUISITION AWARD**

Land Acquisition Case No.

	Name of the Project-					
	Number and date of declaration under which the land is to be acquired					
	Situation and extent of the land in acres, the number of field plots on the survey map, the village in which situated with the number of mile plan if any.					
	Description of land, <i>i.e.</i> , whether fallow, cultivated, homestead, etc. if cultivated, how cultivated? Source of irrigation.					
	Names of persons interested in the land and the nature of their respective interests.					
	Amount allowed for the land itself, without trees, buildings etc, if any					
	Amount allowed out of such sum as compensation for the tenants interest in the land.					
	Basis of calculation:					
	Amount allowed for trees, house or any other immovable property					
	Amount allowed for crops.					
	Additional compensation on the market value under section 30(3)					
	Damages under section 28					
	Solatium under section 30(1)					
	Award under sections 23 and 30					
	Particulars of abatement of Government Revenue, or of the capitalized value paid, the date from which the abatement takes effect.					
	Apportionment of the amount of compensation	Serial No	Name of claimants	Amount payable to each	Bank A/C No.	Remarks
	Area (in acres)				*	
	Date on which possession was taken u/s 38(1) of Act of 30/2013.					

Date:

Seal & Signature of the Collector

*

Bank account detail to be collected in all cases where Aadhaar number is not available or Aadhaar is not seeded in the bank account of the claimant.

FORM-XII*[See rule-27 (1)]***AWARD FOR REHABILITATION AND RESETTLEMENT**

Land Acquisition Case No.

1.	Name of the Project-							
2	Number and date of declaration under which the land is to be acquired							
3.	Situation and extent of the land in acres, the number of field plots on the survey map, the village in which situated with the number of mile plan if any.							
4.	Description of the housing units, transportation cost, housing allowances, annuity, employment subsistence grant, cattle shed, petty shop, one time resettlement allowances etc.							
5.	Name/Names of persons interested in the land and the nature of their respective claim for rehabilitation and resettlement.							
6.	Apportionment of the amount of compensation area (in acres)	Serial Number	Name of claimants/ affected family	R & R entitlements	Bank A/C No.	Amount payable to each	Non monetary entitlements	Remarks
				(i) House to be allotted (ii) Land to be allotted (iii) Fishing rights (iv) Annuity (v) Employment (vi) Transportation cost (vii) Housing allowances, (viii) Subsistence grant (ix) Cattle shed, Petty shop, (x) One time resettlement allowances				
7.	Date on which Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected family.							
8.	Basis of calculation:							
9.	Amount allowed for trees, house or any other immovable things.							
10.	Amount allowed for crops.							
11.	Additional compensation on the market value under section 30(3) of the Act							

12.	Damages under section 28					
13.	Solatium under section 30(1)					
14.	Award under sections 23 and 30					
15.	Particulars of abatement of Government Revenue, or of the capitalized value paid, the date from which the abatement takes effect.					
	Appointment of the amount of compensation	Serial Number	Name of claimants	Amount payable to each	Bank A/C No. *	Remarks
	Area (in hectares)					
16.	Date on which possession was taken u/s 38(1) of the Act.					

Date:

Seal & Signature of the Collector

* **Bank account detail to be collected in all cases where Aadhaar number is not available or Aadhaar is not seeded in the bank account of the claimant.**

FORM-XIII*[See rule-27(3)]*

Format for Provision of Infrastructural Amenities under Rehabilitation and Resettlement scheme for families displaced due to Land Acquisition

Sr. No.	Components	Details of infrastructure amenities
1	Roads	
2	Drainage	
3	Drinking water	
4	Drinking water for cattle	
5	Grazing land	
6	Fair price Shops	
7	Panchayat buildings	
8	Post Offices	
9	Fertilizer storage	
10	Irrigation facilities	
11	Transport facilities	
12	Burial or cremation ground	
13	Toilet points	
14	Electric connections	
15	Nutritional services	
16	Schools	
17	Sub-health centre	
18	Primary Health Centre	
19	Play ground	
20	Community centre	
21	Places of worship	
22	Separate land for tribal institutions	
23	Timber forest produce	
24	Security arrangements	
25	Veterinary services	
26	Any other infrastructure amenity	

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial
Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.